



बस मार्शल द्वारा भेजी गई 11 अगस्त 2023 की एक सरकारी नोटिंग शीट, जानें क्या लिखा है और किसने लिखा है

संजय बाटला

नई दिल्ली। वीरवार को पूरा दिन सड़कों पर आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ सड़क पर बैठकर, धरना देने वाले बस मार्शल दिल्ली के उपराज्यपाल और राजनीतिक दल बीजेपी को अपनी नौकरी जानें के पीछे मुख्य रूप में मान रहे थे और आम आदमी पार्टी इसका भरपूर फायदा भी उठाती आ रही थी पर कल ही किसी ने उस धरने के दौरान बस मार्शल को एक सरकारी दिल्ली सरकार द्वारा लिखित नोटिंग शीट की कापी प्रदान करी जिसे आज उस बस मार्शल द्वारा दिल्ली में चलने वाले कई हटाटसप मुद्राओं में अपनी बात के साथ पोस्ट किया है। आप भी जानें और पढ़ें बस मार्शल के लिखित बयान के साथ

Para 757 and para 758 are in direct contradiction. Para 757 says that legally, civil defence volunteers cannot be used for routine official duties. Para 758 says that 189 civil defence volunteers may be engaged for routine duties of Revenue department.

Engagement of civil defence volunteers is either legal or illegal. If it is illegal, then engagement of 189 is also illegal. If it is legal, then the numbers have to be decided by the government through a proper exercise and not in this ad hoc manner. The correct legal position may be ascertained. Till it is decided, services of all civil defence volunteers may be terminated at the end of Oct.

Regarding making payments for the services rendered till now, the same should be made immediately.

I am shocked to learn that payments have not been made to them for seven months since 1 April. Most of them came from very poor background. Their jobs are very tentative in nature. They can be called anytime for work and they can be asked to stop coming next day suddenly. Imagine the plight of a person who is doing such a tentative job. He must be in a very dire need of money. That's why he is coming for such temporary work. And if we do not pay them in time, we have committed a crime against them. Some officers in the system are so insensitive and so selfish that it is only their own salaries, perks and promotions that matter to them. They are least bothered about the plight of such poor people. They keep playing football with the files. In fact, they derive sadistic pleasure in obstructing work and stopping files.

I recommend exemplary punishment against the officers including the senior most officers in the present case, which are directly or indirectly responsible for this delay. We should give such punishment to these officers that henceforth, any other officers do not indulge in such dilatory tactics. The officers responsible for the delay in this case should be immediately suspended and disciplinary proceedings should be initiated against them.

If Hon'ble LG shares my sentiments, this matter may be placed before the next Authority meeting.

(Arvind Kejriwal)

विजेन्द्र गुप्ता
नेता अधिवक्ता,
दिल्ली विधानसभा
VIJENDER GUPTA
LEADER OF OPPOSITION
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

29, दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110064
29, Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-110064
Tel : 23990250, 23990059
Mob : 9873427234

No.F 2(4) 1 CM 1 Loop 8024/2076
Date: 4th October, 2024

Respected Me Atishi Ji
Namaste

I am writing to inform you that I alongwith other BJP MLAs are visiting your office at Delhi Secretariat tomorrow i.e. on 05.10.2024 at 10.30 AM for an important public issue of reinstatement of services of bus marshals who were deployed in the DTC buses.

We know that tomorrow is Saturday but the matter is so important and sensitive that we can not delay the matter further in public interest.

Kindly make necessary arrangement as per above meeting schedule for fruitful resolution of the issue.

Warm regards,

Yours sincerely,
[Signature]
(Vijender Gupta)

Ms. Atishi Ji
Hon'ble Chief Minister of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

आप लोग खुद देखो इस लेटर को इसमें केजरीवाल जी ने खुद हटाया था सभी बस मार्शल को पिछला ऑर्डर क्यों नहीं कैसिल करवाते दिल्ली सरकार अभी-अभी जानकारी के मुताबिक पता चला है जो पहले का ऑर्डर था बस मार्शल का उसमें केजरीवाल जी ने खुद निकलवाया बस मार्शल को उसके बाद LG साहब ने साइन करे पिछले ऑर्डर को कैसिल कराना होगा क्योंकि पिछले ऑर्डर में सिविल डिफेंस के द्वारा दोबारा नहीं लग सकते क्योंकि बीजेपी ने तो खुद बोला था परामनेट के लिए तो क्यों नहीं पिछला ऑर्डर कैसिल करवाते आम आदमी पार्टी वाले समझो भाइयों और बहनों सभी एक टीम बनाकर सौरभ भारद्वाज जी से और आतिशी मैडम को बोली पिछला ऑर्डर कैसिल करके नए ऑर्डर पर साइन करवाए भाजपा खुद बोल रही है जैसे ही पुराना ऑर्डर कैसिल हो जाएगा आप सब की नौकरी लग जाएगी।

पैरा 757 और पैरा 758 में सीधा विरोधाभास है। पैरा 757 में कहा गया है कि कानूनी तौर पर सिविल डिफेंस वावॉलंटियर्स को नियमित आधिकारिक ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पैरा 758 में कहा गया है कि 189 सिविल डिफेंस वावॉलंटियर्स को रोजाना विभाग के नियमित ड्यूटी के लिए तैयार जा सकता है।

सिविल डिफेंस वावॉलंटियर की नियुक्ति या वेतन है या अवेतन। अगर यह अवेतन है, तो 189 की नियुक्ति भी अवेतन है। अगर यह वेतन है, तो सरकार को उचित प्रक्रिया के जरिए संख्या तय करनी होगी, न कि इस तरह के बदय तरीके से। सही कानूनी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जब तक यह तय नहीं हो जाता, तब तक अक्टूबर के अंत में सभी सिविल डिफेंस वावॉलंटियर की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

अब तक प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करने के संबंध में, इसे तत्काल किया जाना चाहिए।

मुझे यह जानकारी आश्चर्य हुआ कि 1 अगस्त से सात महीने से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। उनमें से अधिकांश बहुत मूल्य पूछभूमि से आते हैं। उनकी जीविकी बहुत ही अस्थायी है। उन्हें कभी भी काम के लिए बुलाया जा सकता है और उन्हें अगले दिन अवेतन देने से नाराज किया जा सकता है। उस व्यक्ति की दुर्दशा की कल्पना करें जो इस तरह का अस्थायी काम कर रहा है। उसे पैसे की बहुत सख्त जरूरत होगी। इसलिए यह इस तरह के अस्थायी काम के लिए आ रहा है। अगर हम उन्हें समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो हमने उनके खिलाफ अपराध किया है। सिस्टम में कुछ अधिकारी इतने अकुशल हैं और इतने स्वार्थी हैं कि उनके लिए केवल उनके अपने वेतन, भत्ते और पदोन्नति ही मान्य रहती हैं। उन्हें ऐसे गरीब लोगों की दुर्दशा की कोई परवाह नहीं है। वे भाइयों के साथ झूठाले खर्चों करते हैं। वास्तव में, उन्हें काम में बाधा डालने और फाइलों को रोकने में परंपरिक आदत मिलती है।

इस मामले में उन अधिकारियों (जिन्होंने विलक्षण अधिकारी भी शामिल हैं) के खिलाफ कठोर सजा की विचारणा करना ही उपयुक्त होगा। इस देश के लिए जिम्मेदार हैं। इन अधिकारियों को ऐसी सजा देने चाहिए कि आगे से कोई भी अन्य अधिकारी इस तरह की दुष्प्रवृत्ति वाली हरकतें न करे। इस मामले में देश के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

यदि माननीय उपराज्यपाल मेरे भावनाओं से सहमत हों तो यह मामला प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जा सकता है।

(अरविंद केजरीवाल)

नोएडा-ग्रेंटर नोएडा एक्सप्रेस-वे का अब नए सिरे से होगा सर्वे, 10 लाख सफर करने वालों को मिलेगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा-ग्रेंटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर हर रोज करीब 10 लाख गुजरते हैं। अब नोएडा प्राधिकरण इन्हें सुरक्षित यात्रा कराने के लिए शानदार इंतजाम करने वाला है। अब इस एक्सप्रेस-वे पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नए सिरे से सर्वे करेगा। अगस्त महीने में संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मानकों में खामियां देखी गई थी। लेख के माध्यम से जानें पूरी खबर।



डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के बाद एक्सप्रेस-वे पर बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

सुरक्षा मानकों में खामियों के उजागर के बाद फैसला नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा मानकों में बदलाव का निर्णय उस सर्वे रिपोर्ट के बाद लिया है, जिसे अगस्त माह में अपर मुख्य कार्यालय अधिकारी (सीआरआरआई) का चयन कर एक्सप्रेस-वे का नए सिरे से सर्वे कराने को लिखा है।

इसमें उन बिंदुओं को प्रमुखता से उजागर करने को कहा है, जो एक्सप्रेस-वे पर वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं।

विद्युत यांत्रिकी विभाग में तैनात अवर अभियंता के दो बेटों सहित उसके मित्र की मौत हुई थी। दैनिक जागरण ने घटना के दिन ही कारण बता दिया था।

हादसे की वजह मानी गई छह परियोजनाएं

हादसे में यातायात पुलिस की गेंद्री पोल के बेस में कार टकरा गई थी, जो बेस गलत तरीके से कैश बैरियर के अंदर बना था। इसके बाद प्राधिकरण सीईओ ने अपर मुख्य कार्यालय अधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की थी। जांच रिपोर्ट में हादसों का कारण छह परियोजनाओं को माना गया है।

इसमें जितने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एवं

ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) के पोल, जिसमें यातायात पुलिस कैमरों से कंट्रोल रूम से निगरानी व ई-चालान किया जा रहा है। यातायात नियमों की जानकारी के लिए पुलिस की ओर से लगाई गई गेंद्री, नोएडा ट्रैफिक सेल की ओर से लगाई गई मार्ग निर्देशिका, जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से बनवाए गए सार्वजनिक शौचालय सभी नियम विरुद्ध बने हैं।

एक्सप्रेस-वे से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) के पोल, बाह्य विज्ञापन के यूनीपोल, फुटओवर ब्रिज, साइन बोर्ड, सार्वजनिक शौचालय, यातायात पुलिस की गेंद्री का स्थान बदलने की बात कही थी।

एक्सप्रेस-वे पर सड़क सुरक्षा मानकों को सही कराया जाए। इसके लिए सीआरआरआई को नए सिरे से सर्वे कराने को कहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मानकों को दुरुस्त कराया जाएगा।

संजय कुमार खत्री, अपर मुख्य कार्यालय अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण

नमो भारत में सफर करना हुआ अब और भी आसान, अब 'ऑल इन वन कार्ड' का करें इस्तेमाल

एनसीआरटीसी मुख्यालय गति शक्ति भवन में एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी गणेश अनंतनारायणन ने एनसीएमसी कार्ड लांच किए। इन कार्ड में डेबिट प्रीपेड और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मास ट्रांजिट साल्यूशन (पीपीआई-एमटीएस) के विकल्प शामिल हैं। इस कार्ड के जरिए नमो भारत सहित कई सार्वजनिक वाहनों में सफर कर सकते हैं।



नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर को-ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) तैयार किया है।

गुरुवार को एनसीआरटीसी मुख्यालय गति शक्ति भवन में एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक

शलभ गोयल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी गणेश अनंतनारायणन ने यह कार्ड लांच किए। इन कार्ड में डेबिट, प्रीपेड और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मास ट्रांजिट साल्यूशन (पीपीआई-एमटीएस) के विकल्प शामिल हैं।

इस कार्ड से कई सार्वजनिक परिवहन में होगा इस्तेमाल

इस अवसर पर एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा, 'इस ऑल-इन-वन कार्ड के साथ यात्री नमो भारत एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। साथ ही रोमरों की जरूरतों

की पूर्ति हेतु भुगतान के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।"

पीएम मोदी की पहल का है हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी की 'वन नेशन, वन कार्ड' पहल के तहत लॉन्च किए गए इस कार्ड से यात्रा करना और भी सुलभ होगा। बता दें, वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर का 42 किमी का हिस्सा संचालन में है। वहीं मेरठ मेट्रो के साथ-साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर अगले वर्ष जून 2025 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगी। इसका ट्रायल इसी साल होना प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता: स्वयं की सुरक्षा और समाज के लिए बनें सड़क सुरक्षा स्वयंसेवक



आज के तेजी से बदलते दौर में, सड़कें न केवल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं, बल्कि इनका उपयोग हर दिन लाखों लोग करते हैं। हर कोई अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना चाहता है, लेकिन सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और लापरवाह ड्राइविंग ने इसे एक चुनौती बना दिया है। इसी चिंता के मद्देनजर, परिवहन विशेष और रोड सेफ्टी स्क्वाड ने एक संयुक्त पहल के रूप में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह पहल आपको और आपके परिवार को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने और इस दिशा में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सड़क सुरक्षा: समय की मांग

भारत में सड़क दुर्घटनाएं हर दिन कई जीवन ले रही हैं। चाहे वह तेज गति हो, बिना हेलमेट के बाइक चालना हो, या शराब पीकर गाड़ी चालना, इन सभी खतरनाक आदतों के कारण अनगिनत परिवारों को दर्द और नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बन चुकी है।

सड़क सुरक्षा स्वयंसेवक बनें

परिवहन विशेष और रोड सेफ्टी स्क्वाड के इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करना है। स्वयंसेवक के रूप में, आप सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, सही ड्राइविंग आदतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं



और अपने आसपास के लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

क्यों बनें स्वयंसेवक ?

समाज के प्रति योगदान: स्वयंसेवक बनकर आप समाज को एक सुरक्षित परिवेश देने में मदद कर सकते हैं।

स्वयं की सुरक्षा: जब आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, तो न केवल आप अपनी, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।



चैनमेकर बनने का अवसर: इस पहल का हिस्सा बनकर आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं।

स्थानीय मुद्दों को उठाएं: 'वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी' का संदेश देते हुए आप अपने इलाके के सड़क सुरक्षा मुद्दों को उजागर कर सकते हैं और उनके समाधान के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

अपनी कहानी साझा करें

इस अभियान के तहत, परिवहन विशेष और रोड सेफ्टी स्क्वाड आपको आर्मात्रित करते हैं कि आप अपनी सड़क सुरक्षा से जुड़ी कहानी साझा करें। हो सकता है आपने किसी सड़क दुर्घटना से खुद बचाया हो, या किसी को जागरूक करने में मदद की हो। आपकी कहानी न केवल दूसरों को प्रेरित करेगी, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी प्रसारित करेगी।

जिम्मेदारी आपकी और हमारी

सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन का कार्य नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यह समय है कि हम सभी सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता से सोचें और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सड़क पर



जिम्मेदार नागरिक बनें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

आइए, इस सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का हिस्सा बनें और स्वयंसेवक बनकर अपने समाज को सुरक्षित बनाएं। याद रखें, सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन बचाने का साधन है।

“रोड सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, आइए मिलकर एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें।”

डॉ. अंकुश शरण, सड़क सुरक्षा और



लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ, के नेतृत्व में रोड सेफ्टी स्क्वाड एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में उभर रहा है। इसमें छात्रों, कॉरपोरेट्स, संस्थानों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़ सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति समर्पण और जुनून रखने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करना है। सर्वश्रेष्ठ कहानियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाएगी और ये लोग देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। यदि आपके पास सड़क सुरक्षा के प्रति समर्पण है, तो इस परिवर्तनकारी पहल का हिस्सा बनें।

इनसाइड



काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ रहा है वजन, महिलाएं फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से होगा वेट गेन

दुबली-पतली महिलाएं आमतौर पर वेट गेन करने के लिए अनगिनत नुस्खे आजमाती हैं, मगर हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है।

स्लिम एंड टिम लुक कैरी करने के लिए महिलाएं कई तरीके अपनाती हैं। इसके बावजूद कुछ महिलाएं मोटापा का शिकार होने लगती हैं। तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं। अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इन चीजों को डाइट में शामिल करने आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं।

पतली और दुबली महिलाएं अक्सर अपने फिगर को लेकर टशन में रहती हैं। वहीं पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के बाद भी कई बार महिलाओं का वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता है। ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है। तो आइए जानें मोटापे से निपटारे के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके महिलाएं खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं।

प्रोटीन का सेवन करें

नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बाँडी का वेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है। खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शुगर और फैट भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है, जिससे मसल्स बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है। ऐसे में आप पनीर, फुल क्रीम मिल्क, दही और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल कर सकती हैं। साथ ही चिकन, अंडा, लाल मीट, मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर जैसे चीजों से आप आसानी से वेट गेन कर सकती हैं।

फैट रिच डाइट लें

वजन बढ़ाने के लिए महिलाएं फैट से भरपूर चीजों को भी डाइट में एड कर सकती हैं। ऐसे में घी, मक्खन, नट्स और गुड फैट से भरपूर चीजों का सेवन करना महिलाओं के लिए बेस्ट होता है। इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और महिलाओं के वजन में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है।

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाएं

कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें बाँडी में कैलोरी इन टेक को बढ़ावा देती हैं। जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में वेट गेन करने के लिए महिलाएं आलू, शकरकंद, आटे, भूत आर आउन राइस का सेवन कर सकती हैं। वहीं घी और बटर से युक्त चीजें खाने से भी वेट गेन फास्ट होने लगता है।

वजन ना बढ़ने के कारण

महिलाओं में वजन ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। दरअसल कई बार महिलाओं के शरीर में मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से एजॉबैक नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हेल्दी डाइट लेने के बावजूद महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है और उनका वजन कम रहता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और हाइपोथायरायडिज्म के चलते भी महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है।

प्रो. मनोज डोगरा

प्रत्येक पुरुष को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाओं के उत्थान व विकास में अपनी भूमिका सिद्ध करनी चाहिए तथा अपना शत-प्रतिशत योगदान महिलाओं के विकास व उत्थान में देना चाहिए ताकि महिलाएं अकेला महसूस न करें।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ देश की भूमि की कल्पना ही एक नारी अर्थात् भारत माँ के रूप में की जाती है और भारत माता के रूप में ही पूजा भी जाता है। ऐसा राष्ट्र व समाज जहाँ प्राचीन समय से ही नारी की देवी के रूप में पूजा की जाती है तथा नारी को देवतुल्य समझा जाता है, लेकिन जैसे-जैसे वक्त का पहिया घूमा, समाज में देवी रूपी महिलाओं को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो, अपराध हो या दहेज के लिए शोषण हो। इन धारणाओं से समाज में महिला सशक्तिकरण की आवाज आज बुलंद हुई है। इसमें सबसे विशेष तो यह है कि सशक्तिकरण तो महिलाओं का होना है, लेकिन इसमें अहम भूमिका पुरुषों ने निभानी है। यह भूमिका एक पुरुष बतौर पिता, पुत्र, भाई, पति व मित्र इत्यादि के रूप में निभाएंगे। अगर पुरुष इन भूमिकाओं की अदायगी एक आदर्श रूप में करें तो स्वतः ही महिलाओं के जीवन स्तर में उत्थान व विकास तीव्र गति से होगा। लेकिन महिलाओं को भी अपने लिए सशक्त होने की आवश्यकता है। कुछ महिलाएं अपने घर तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन जब एक पुरुष उस महिला को शक्ति प्रदान कर उसके साथ चलता है तो स्थिति में बदलाव आता है। इस स्थिति को सही मायने में सशक्तिकरण का नाम दिया जाता है।

महिलाएं परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होकर अपने सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार तक को त्यागने लग जाती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उसका साथ देने के लिए कोई खड़ा होता है तो एक पिता होता है व एक पुत्र होता है या फिर एक शिक्षक होता है।

समाज में रूढ़िवादी सोच का पिढारा सिर पर लिए घूमते बहुत लोग नजर आएं, लेकिन उसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के प्रति सम्मान और बराबरी की सोच रखते हैं। आज हर जगह चाहे वह गांव हो या शहर, प्रत्येक जगह महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, लेकिन जिस गति से सुधार की परिकल्पना की जाती है, वैसा सुधार अभी तक देखने को नहीं मिलता। महिलाएं सामाजिक परिवेश में विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि समाज उन्हें नजर अंदाज करता है। लेकिन समाज में साथ देने वाले लोग होंगे तो भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है, जिससे नारी सशक्तिकरण अवश्य होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल आबादी की 48.1 फीसदी आबादी महिला आबादी है। जब देश की आधी आबादी संकट में हो तो शेष आबादी का यह कर्तव्य बनता है कि वे चुप न बैठकर इनके उत्थान व विकास में अपना योगदान दें। पुरुषों के महिला सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण को उदार बनाना अत्यंत आवश्यक है। समाज के अधिकांश पुरुष महिलाओं के विकास हेतु अपना शत-प्रतिशत योगदान दे रहे हैं तथा पहले भी दिया है। इनमें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी इत्यादि महान पुरुष हैं जिनसे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है। इसी श्रेणी में स्वामी विवेकानंद व गुरु नानक देव जी का भी नाम शामिल है। इन्होंने महिला समानता जैसे विषयों को समाज के समक्ष उजागर किया था तथा महिला व पुरुष को



महिला सशक्तिकरण

एक बराबर अधिकार देने की बात कही थी। महिला सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, लेकिन इसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था सामने उजागर हो जाती है कि महिलाएं देश में आज कितनी सुरक्षित हैं।

लंबे समय से समाज के अधिकांश पुरुष महिलाओं के विकास हेतु अपना शत-प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। वे महिलाओं के लिए एक ऐसा स्वच्छ माहौल

प्रदान कर रहे हैं जिसमें महिलाएं अपने पंखों को खोल सकें और ऊंची उड़ान भर सकें। वर्तमान की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है जिनसे महिलाओं में खुशी की लहर व एक नई उमंग व सुरक्षा का भाव देखने को मिलता है। चाहे वो तीन तलाक जैसे विषय पर कानून बनाना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, उज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी

महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनसे राष्ट्र की महिलाओं के जीवन स्तर में अनेक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। आधुनिक समय में फिल्मों के जरिए भी महिलाओं के विषयों पर चर्चा हो रही है। पिक टॉयलेट, वेगम जान, गुलाबी गैंग व बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों ने भारतीय समाज को आईना दिखाया है तथा महिलाओं के हितों व समस्याओं को समाज के समक्ष रखा है। वर्तमान का समय एक

ऐसा समय है जिसमें महिलाएं हर क्षेत्र में अपना शत-प्रतिशत योगदान दे रही हैं, चाहे वह सेना का क्षेत्र हो, प्रशासनिक सेवा में सेवाएं देना हो, ग्रामीण विकास हो, शिक्षा क्षेत्र हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो। एक सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज निर्माण तक का कार्य महिलाएं कर रही हैं। यहां तक कि हवाई जहाज भी आज की महिलाएं उड़ा रही हैं। देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति जी एक महिला हैं। साथ ही देश की आर्थिक को एक महिला संभाल रही है। इसके बावजूद कहना होगा कि समाज द्वारा तब भी उन्हें कमजोर समझा जाता है।

उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें उपयोग की वस्तु समझा जाता है, जो कि सरासर गलत है। समाज के प्रत्येक पुरुष को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाओं को अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं। अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इन चीजों को डाइट में शामिल करने आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं।

उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें उपयोग की वस्तु समझा जाता है, जो कि सरासर गलत है। समाज के प्रत्येक पुरुष को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाओं को अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं। अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इन चीजों को डाइट में शामिल करने आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं।

महिलाओं में 5 बीमारियों को देता है दावत मोटापा, समय रहते कर लें कंट्रोल, वरना हो सकते हैं गंभीर परिणाम

आजकल खराब लाइफस्टाइल और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण अधिकतर पुरुष-महिलाएं वजन बढ़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। यदि वजन बढ़ने को समय रहते कंट्रोल ना कर लिया जाए, तो आप मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। मोटापा कई बीमार को जन्म देता है। वजन बढ़ने की समस्या महिलाओं में भी अधिक देखी जाती है। दरअसल, हाउस वाइफ में वजन बढ़ने की समस्या अधिक देखी जाती है, क्योंकि ये घर के काम में तो व्यस्त रहती हैं, लेकिन शरीर को फिट रखने और बाँडी वेट को बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहती हैं। यदि आप घर पर रहेंगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगी, चलना-फिरना कम होगा तो वजन बढ़ सकता है। एक बार आप मोटापे की शिकार हो गईं तो कई तरह की गंभीर बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं।

मोटापा के कारण

वृमसेहेल्थ डॉट जीओवी के अनुसार, ओबेसिटी या मोटापे की समस्या तब शुरू होती है, जब शरीर समय के साथ उपयोग

की तुलना में कैलोरी को अधिक मात्रा में जमा करता है। आपके शरीर को ठीक से काम करने और सक्रिय रहने के लिए कैलोरी और आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपका शरीर उपयोग की तुलना में अधिक कैलोरी जमा करता है, तो आपका वजन बढ़ने लगता है। यदि बढ़ते वजन पर समय

रखते ना कंट्रोल किया जाए तो यह मोटापे का रूप ले सकता है। आप बाँडी मास इंडेक्स (BMI) का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि आपका वजन अधिक है या फिर मोटापे से ग्रस्त हो चुकी हैं। बीएमआई हेल्दी और अनहेल्दी रेंज का पता चलता है। यह एक ऐसा टूल है, जो बाँडी फैट का सही से अनुमान लगाता है। इसका पता आपको बीएमआई कैल्कुलेटर से चल सकता है।

— 25 से 29.9 बीएमआई होने का मतलब है कि आपका वजन अधिक है।

— 30 या उससे अधिक बीएमआई



होने का मतलब है कि आप मोटापे से ग्रस्त हैं।

महिलाओं में वजन बढ़ने के खतरे एनटीवी डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, यदि आप लंबी उम्र तक बीएमआई हेल्दी और अनहेल्दी रेंज का पता चलता है। यह एक ऐसा टूल है, जो बाँडी फैट का सही से अनुमान लगाता है। इसका पता आपको बीएमआई कैल्कुलेटर से चल सकता है।

मोटापा मुख्य रूप से जेनेटिक्स, उम्र, हॉर्मोनल बदलाव, प्रेग्नेसी के दौरान वजन बढ़ना, पीसीओएस डिऑर्डर आदि के कारण हो सकता है। शुरुआत से ही वजन को कंट्रोल में रखने के उपायों को अपनाकर आप काफी हद तक मोटापे से ग्रस्त होने से बच सकते हैं।

अत्यधिक वजन और मोटापा को कंट्रोल करने के उपाय

— आप प्रतिदिन हेल्दी डाइट लेकर और अत्यधिक वजन होने से महिलाओं की सहेत पर नेगेटिव असर पड़ता है। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। मूड प्रभावित होता है। पल्मोनरी फंक्शन सही नहीं रहती है। बढ़ता वजन आपको कई तरह की गंभीर बीमारी दे सकता है जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, पीओएस, प्रेग्नेसी, गठिया, से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मोटापा गुणवत्ता और जीवन काल को कम कर सकता है।

लेनी चाहिए। लो-कैलोरी डाइट जो हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर हो वह आपको हेल्दी रखने में कारगर साबित हो सकती है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, बावजूद इसके आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। वजन को कंट्रोल में रखने के लिए आप सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अधिक देर तक बैठे रहने, लेटे रहने की आदत को दूर करें। प्रत्येक 20 मिनट में 3 से 5 मिनट तक चल-फिर लें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बना रहेगा।

— आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले सकती हैं। इसके लिए किसी डाइटिशियन से सलाह लें। साथ ही खुद को हाइड्रेटेड बनाए रखें। रात में सोने से पहले शुगरी ड्रिंक, कैफ़ीन का सेवन ना करें। जंक फूड, शुगरी स्नैक्स, फ्राइड फूड कम खाएं और हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, लीन प्रोटीन जैसे चिकन, फिश, वींस, सोया का अधिक सेवन करें।

कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक टेक्नीक से बाल-बाल बची ब्रिटनी विलियम्स की जान, अपनी स्टोरी शेयर कर कही, ना करें 2 सफेतों को इग्नोर

कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है।

आज लोगों में कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। कम उम्र में ही पुरुष हों या महिलाएं, हर कोई हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को सही से पहचान पाने के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि, ब्राजील की रहने वाली ब्रिटनी विलियम्स नाम की महिला की किस्मत इस मामले में अच्छी साबित हुई थी। मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था। वह अचानक बेहोश हो गई थीं और आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दो दिनों के बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उन्हें

कार्डियक अरेस्ट आया था। टूटे डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, मात्र 24 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण ब्रिटनी विलियम्स की जान जाने ही वाली थी। यह घटना वर्ष 2014 की है। पूरे 9 वर्ष बाद ब्रिटनी ने अपनी कार्डियक अरेस्ट के दौरान हुई स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित जानकारी टुडे शो में एक इंटरव्यू के दौरान साझा की है। ब्रिटनी ने शो में उन लक्षणों के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। जब ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उस दौरान उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं हुए। अचानक वो बेहोश हो गईं। इंटरव्यू में वो बताती हैं कि यदि उन्हें तुरंत कार्डियक अरेस्ट के संकेत का डिटेक्ट कर लिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती। ब्रिटनी ने शो में सीपीआर ट्रेनिंग लेने के महत्व पर भी जोर दिया।

कार्डियक अरेस्ट के संकेत

कार्डियक अरेस्ट तब होता है, जब एलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण हृदय की भर्ती कराया गया था। दो दिनों के बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उन्हें

फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (यूस) के अनुसार, लगभग 90% लोग जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट आता है, उनकी मौत हो जाती है। यदि सही समय पर पीड़ित को सीपीआर दे दिया जाए तो काफी हद तक जान बचाई जा सकती है। इसके लिए सीपीआर देने के बाद तुरंत ही दिल को सामान्य लय में वापस लाने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग भी करना चाहिए। लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक समझने की गलती कर बैठते हैं। हार्ट अटैक तब आता है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो। हालांकि, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिना किसी वॉरनिंग साइन के आ सकता है। लेकिन, ब्रिटनी ने कुछ लक्षणों को इग्नोर करने की भूल की जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने से पहले महसूस हुए थे। ब्रिटनी ने किया इन लक्षणों को नजरअंदाज ब्रिटनी ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह काम कर रही थीं, तब शरीर के बाईं ओर सुनपन, झुनझुनी और सनसनी जैसे लक्षणों को महसूस किया था। इलाज करने के बाद पता



चला कि ब्रिटनी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम (QT syndrome) से ग्रस्त थीं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसमें हार्टबीट तेज और अनियमित हो जाता है। अधिकतर लोग लक्षणों को इग्नोर करते हैं। कई बार यह दवाओं के कारण भी हो सकता है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार इसे सीजर (seizure) या मिर्गी समझ लिया जाता है। इसका इलाज दवाओं पर था, तब शरीर के बाईं ओर सुनपन, झुनझुनी और सनसनी जैसे लक्षणों को महसूस किया था। इलाज करने के बाद पता

अचानक बेहोश होकर गिर जाना नाड़ी का रुक जाना सांस का रुकना कार्डियक अरेस्ट आने से पहले सीने में तकलीफ सांस लेने में तकलीफ महसूस करना कमजोरी महसूस करना दिल का तेजी से धड़कना इस तरह के लक्षण यदि आपको कभी भी नजर आएं, तो भूलकर भी इग्नोर ना करें। ये कार्डियक अरेस्ट आने से पहले के संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोग इन लक्षणों को

नजरअंदाज कर देते हैं जैसा कि ब्रिटनी के मामले में हुआ। ब्रिटनी ने भी कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर में सुनपन, झुनझुनी या सनसनी जैसे लक्षण महसूस किए थे, लेकिन उसने लोगों की कही हुई बातों के आधार पर इन लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया था। कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर का महत्व जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास तुरंत कोई मेडिकल हेल्प पहुंच जाए। कार्डियोपल्मोनरी रिस्पिटेशन यानी सीपीआर (CPR) ऐसे में लाभ पहुंचाता है। कार्डियोपल्मोनरी रिस्पिटेशन हार्ट को कम्प्रेसन देकर एक विद्युत आवेग बनाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय दोबारा से पंप करने लगता है। ऐसे में आज हर किसी को सीपीआर देने की टेक्नीक को सीखना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप पीड़ित की जान बचाने में सफल हो सकें। ब्रिटनी विलियम्स भी अब कुछ ऐसा ही करने में जुटी हुई हैं, ताकि उन्हीं की तरह दूसरे लोगों की भी जान बच सकें।

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर रविवार को देरी से चलेगी मेट्रो, डीएमआरसी ने बताई टाइमिंग

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर रविवार को मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया गया है। येलो लाइन पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है। DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की है। यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए इस खबर में हम आपको पांच बिंदुओं में बताएंगे कि DMRC ने क्या कहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन पर रविवार के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया है। इससे परेशानी हो सकती है। इससे परेशानी हो सकती है। इससे परेशानी हो सकती है।

DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस खबर के माध्यम से पांच बिंदुओं में समझे डीएमआरसी (DMRC) द्वारा दी गई टाइमिंग के बारे में।

DMRC ने दी जानकारी
येलो लाइन (समयपुर बादली - मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम) पर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर नियोजित रखरखाव कार्य करने के लिए, येलो लाइन पर ट्रेन सेवाओं को 6 अक्टूबर,



2024 (रविवार) की सुबह 6:40 बजे तक संक्षिप्त रूप से विनियमित किया जाएगा। निम्नलिखित योजना के अनुसार:

1. 6 अक्टूबर 2024 रविवार को पहली ट्रेन सेवा विश्वविद्यालय से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक सुबह 6:00 बजे के बजाय 6:45 बजे और कश्मीरी गेट से समयपुर बादली तक सुबह 6:00 बजे के बजाय 06:52 बजे शुरू होगी।

2. विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशनों के बीच और इसके विपरीत कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं होगी। दो स्टेशन यानी विधानसभा और सिविल लाइन्स ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होने यानी सुबह 6:40 बजे तक बंद रहेंगे।

10 मिनट की देरी से मिलेगी ट्रेन सेवाएं

3. हालांकि, येलो लाइन के शेष प्रमुख खंड मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से कश्मीरी गेट और समयपुर बादली से विश्वविद्यालय स्टेशनों पर सामान्य ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

4. रखरखाव कार्य के दौरान, ट्रेन सेवाएं 10 मिनट की देरी पर उपलब्ध होंगी और उसके बाद, शेष दिन के लिए नियमित रविवार की समय सारिणी का पालन किया जाएगा।

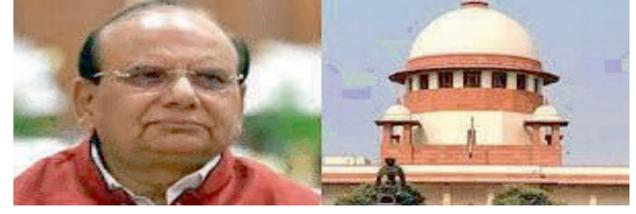
5. 6 अक्टूबर को सुबह के समय यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए, इस रखरखाव अवधि के दौरान परिवर्तन के लिए ट्रेनों के गंतव्य और संबंधित प्लेटफार्मों के बारे में येलो लाइन पर स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर घोषणाएं भी की जाएंगी।

'इतनी जल्दी क्यों थी?' सुप्रीम कोर्ट ने MCD पैनल चुनाव पर LG सक्सेना को लगाई फटकार; जवाब भी मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वह इसी तरह हस्तक्षेप करते रहे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। दरअसल एलजी ने स्थायी समिति की 18वीं सीट का चुनाव तुरंत कराने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वह एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इसी तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन को पीठ ने कानून के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल द्वारा चुनाव का आदेश देने के पीछे के आधार पर भी सवाल उठाया। पीठ ने



कहा, रनामंकन का मुद्दा भी है... मेयर (सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय) अध्यक्षता करने के लिए वहां मौजूद हैं। आपको (एलजी को) शक्ति कहां से मिलती है?"

18वीं सीट के लिए तत्काल चुनाव करने का था आदेश
बता दें, पिछले हफ्ते सदन में जोरदार ड्रामा चला था। दरअसल, एलजी सक्सेना ने स्थायी समिति की 18वीं सीट का चुनाव तुरंत कराने का आदेश दिया था और इसमें भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी। जबकि मेयर शैली ओबेरॉय ने सदन भंग कर दिया था। इस चुनाव का आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था। बाद में मेयर ने

एलजी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

स्थायी समिति के अध्यक्ष का चुनाव न कराने को कहा

पीठ ने कहा, रइस तरह हस्तक्षेप करने से लोकतंत्र का क्या होगा? क्या इसमें भी कोई राजनीति है? सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी समिति में भाजपा के सुंदर सिंह त्वर के चुनाव को चुनौती देने वाली सुश्री ओबेरॉय की याचिका पर श्री सक्सेना से जवाब भी मांगा। वहीं कोर्ट ने एलजी कार्यालय से कहा कि इस मामले की सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष का चुनाव न होने दें। इसका नोटिस अभी जारी करें।

सावधान! राजधानी में बेकाबू हुआ डेंगू, एक हफ्ते में आए 400 से ज्यादा नए मामले

दिल्ली में डेंगू के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 22 से 28 सितंबर के बीच 400 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इस साल अब तक डेंगू से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है। राजधानी के लोगों को इस समय संभलकर रहने की जरूरत है।

राजधानी में डेंगू के मामलों में बढ़ गए हैं। 22 से 28 सितंबर के बीच 401 नए मामले दर्ज हुए हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी वृद्धि हुई है। एमसीडी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 1,630 तक पहुंच गए हैं।

15 से 21 सितंबर तक, शहर में करीब 300 मामलों की साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई थी। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उसके बाद नजफगढ़ क्षेत्र है। दिल्ली में 22-28 सितंबर की अवधि में मलेरिया (Malaria in Delhi) के 67 नए और चिकनगुनिया के 13 मामले सामने आए हैं।

इस साल 28 सितंबर तक मलेरिया के 430 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2023 में इसी अवधि के दौरान 321



मामले दर्ज किए गए थे। चिकनगुनिया (Chikungunya in Delhi) के मामलों में भी वृद्धि हुई है।

इस साल इसी अवधि में 55 मामले दर्ज किए गए हैं, पिछले साल इसी अवधि में 24 मामले दर्ज हुए थे। इस साल अब

तक डेंगू से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है।

भारद्वाज अस्पताल, नोएडा के फिजीशियन एडीज मच्छर, विशेष रूप से एडीज एंजिटी, जो गर्म, ह्यूमिड जगहों में पाए जाते हैं, के काटने से डेंगू का प्रकोप

शुरू होता है। जमा हुआ पानी, खराब वेस्ट मैनेजमेंट और अपर्याप्त मच्छर नियंत्रण विधियों जैसी चीजों के कारण यह वायरस तेजी से फैलता है। डेंगू का मच्छर हमारे घर के बाहर पानी साफ जगह पर बनाता है। डेंगू का मच्छर दिन में ज्यादा काटता है।

डिजिटल साउंड और हैरत एंजेज ऐक्शन के साथ हुआ ताड़का वध



सुष्मा रानी

नई दिल्ली। लाल किला ग्राउंड में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार ने बताया दूसरे दिन लीला के विशाल मंच पर ताड़का वध और सुबाहु वध के एक्शन सींस को सजीव और जीवंत बनाने के लिए बॉलिवुड फिल्मों के मशहूर एक्शन डायरेक्टर मनोज कांगड़ा की निगरानी में डिजिटल साउंड और कम्प्यूटर ग्राफिक्स का ऐसा जानदार प्रयोग किया गया कि मैदान में बैठे हजारों राम भक्तों ने जमकर तालियां बजाईं।

आज लीला अवलोकन के लिए माननीय श्रीपद नायक, विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मंत्री ने प्रभु श्री राम को तिलक कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और कहा राम की लीलाएं

भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं।

लीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के अनुसार आज भव्य मंच पर मुम्बई फिल्म नगरी और टीवी के मझे हुए कलाकारों द्वारा पुत्र यज्ञ के लिए श्रीगंभीर को बुलाना, अग्नि देव प्रकट होकर पायस देना, राम जन्म, नामकरण संस्कार, विश्वामित्र यज्ञ में विघ्न से लेकर ताड़का वध, मारीच युद्ध, सुबाहु वध, की लीला का मंचन हुआ।

लीला मंचन के उपरान्त कमेटी महासचिव सुभाष गोयल, पवन गुप्ता चैयरमैन, सत्य भूषण जैन, सौरव गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अंकुर गोयल कोषाध्यक्ष, प्रवीण सिंगल लीला मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंच पर प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा अर्चना की और आज आए सभी अतिथियों का स्वागत किया।

'अच्छा चलता हूं...!', CM हाउस से केजरीवाल विदा, सुनीता ने सौंपी चाबी तो भावुक हुआ स्टाफ, तस्वीरों में देखें नया आशियाना



केजरीवाल ने शुक्रवार को सीएम आवास खाली कर दिया है। अब केजरीवाल अपने परिवार के साथ नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। शुक्रवार को अपने परिवार के साथ केजरीवाल नए घर पहुंचे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बंगले का ताला खोला। इस दौरान यहां पर लोगों ने केजरीवाल और उनके परिवार का

स्वागत किया। आइए आपको नए बंगले की तस्वीरें दिखाते हैं।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज यानी शुक्रवार को नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने आज ही सीएम आवास छोड़ा है। केजरीवाल अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए हैं।

सीएम आवास से विदा हुए केजरीवाल
शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सीएम आवास से विदा हो गए। विदाई से पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास का ताला लगाया और चाबी

स्टाफ को सौंप दी।

केजरीवाल की विदाई पर भावुक हुआ स्टाफ
वहीं विदाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने चाबी सौंपी तो पूरा स्टाफ भावुक हो गया। इस दौरान सभी ने केजरीवाल और उनके परिवार से हाथ जोड़कर नमस्कार किया।

सभी कर्मचारियों से गले मिले केजरीवाल
इस दौरान अरविंद केजरीवाल सभी कर्मचारियों से एक-एक करके मिले। केजरीवाल ने सभी कर्मचारियों को गले से लगाया और फिर सीएम आवास से विदा हो गए।

अब यह है केजरीवाल का नया ठिकाना

अरविंद केजरीवाल अब लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर पांच में रहेंगे। यह बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आप के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था।

नया आवास नई दिल्ली विधानसभा में है
केजरीवाल का नया आवास रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय के नजदीक है। इस आवास में वह अपने परिवार के साथ रहेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां

रहते हुए वह दिल्ली और अन्य राज्यों में आगामी चुनावों के लिए आप के अभियान की देखरेख करेंगे।

सिसोदिया ने भी अपना बंगला छोड़ा
वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया ने अपने परिवार के साथ मथुरा रोड स्थित एबी-17 बंगले को छोड़ दिया, जो पहले उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में आवंटित किया गया था। मार्च 2023 में आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यह बंगला दिल्ली सरकार की मंत्री और अब मुख्यमंत्री आतिशो को आवंटित किया गया था।

जीडीए में कागजी नहीं, अब ई-ऑफिस के जरिए ऑनलाइन होंगे फटाफट काम; कोई भी फाइल नहीं रुकेगी

परिवहन विशेष न्यूज

जीडीए ने अपने कार्यों को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत की है। अब म्यूटेशन और कार्यालय से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे लोगों के काम तेजी से होंगे और कोई भी फाइल वहीं नहीं रुकेगी। सभी डेटा को भी ऑनलाइन किया जाएगा जिससे कि व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा सके।

गजियाबाद। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देशन में शुक्रवार को चीफ इंजीनियर कार्यालय को ई-ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। इसके तहत म्यूटेशन (नाम दर्ज) और कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जाएंगे। प्राधिकरण सभागार में संबंधित अधिकारियों और स्टाफ के साथ बैठक की।

विकास प्राधिकरण में ई-ऑफिस की शुरुआत चीफ इंजीनियर कार्यालय से की गई है। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लते हुए कहा कि एक-एक कर जल्द ही जीडीए के सभी अनुभाग को ई-ऑफिस में तब्दील किया



जा रहा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को चीफ इंजीनियर कार्यालय से हुई है।

कोई फाइल कहीं न दब सकेगी और

रुकेगी। इसमें पारदर्शिता के साथ कार्य की गति कम नहीं होगी। प्राधिकरण के सभी कामों के ऑनलाइन हो जाने से इसका फायदा आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को भी होगा। विभाग में 20 से ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं हैं। इन सभी की जानकारी फाइलों में है। अब इन

फाइलों को सभी डेटा को भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कि व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा सके।

अभी जानकारी लेने के लिए बाबू को पड़ता है बुलाना

उन्होंने कहा कि अभी किसी भी संबंध में

जानकारी लेने के लिए बाबू को बुलाना पड़ता है। उसके नहीं रहने पर काम में देरी होती है और काम बढ़ता जाता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था प्राधिकरण के सभी अनुभागों में जाएगी। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति अनुभाग, नियोजन, उद्यान, विधि समेत अन्य अनुभाग शामिल होंगे।

जिला अस्पताल में एक ही दिन में बुखार के 500 से अधिक मरीज पहुंचे, एक मासूम की मौत

गजियाबाद में बुखार का कहर जारी है। जिला अस्पताल में एक ही दिन में 500 से अधिक मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें से 25 मरीजों को भर्ती कर लिया गया है। डेढ़ साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई। बच्चा छत से गिरकर घायल हो गया था। अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 2466 मरीजों में से 524 मरीज बुखार से पीड़ित थे। गजियाबाद। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में शुक्रवार को बुखार के पांच सौ से अधिक मरीज पहुंचे। 25 मरीजों को भर्ती किया गया है। जिला एमएमजी अस्पताल को इमरजेंसी में 102 मरीज पहुंचे। जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कैलाश नगर की रहने वाली मुस्कान अपने डेढ़ वर्ष के बेटे रिहान को लेकर इमरजेंसी में पहुंची। जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने चिकित्सकों को बताया कि बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। ओपीडी में पहुंचे 2466 मरीजों में बुखार के 524 मरीज शामिल हैं। संयुक्त अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 1029 मरीजों में बुखार के 103 मरीज पहुंचे। 134 बच्चों समेत 330 लोगों ने एंटी रेबीज वैकसीन लगवाई। जिला एमएमजी अस्पताल की डिजिटल एक्स-रे मशीन पिछले आठ दिनों से खराब पड़ी है। मरीज एक्स-रे कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। ओपीडी में चिकित्सकों द्वारा रोज सौ से अधिक मरीजों का एक्स-रे करने की परामर्श दी जाती है। उधर सीएमएस डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि मेटेन्स कंपनी को तीन बार फ़ोन कर मशीन ठीक कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

नवरात्र और दशहरा को लेकर नोएडा पुलिस ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें पूरा अपडेट



नवरात्र और दशहरा के अवसर पर नोएडा पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिले के मंदिरों और पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस नवरात्र (Navratri 2024) व दशहरा (Dussehra 2024) को लेकर अलर्ट है। जिले के मंदिरों व पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। त्योहार पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हों। तीनों जोन के सभी थानों में नवरात्र से पूर्व मंदिर प्रबंधन, पीस कमेटी और दुर्गा पूजा समिति पदाधिकारियों संग बैठक होने का सिलसिला जारी है। पुलिस अधिकारियों की ओर से मंदिर और आयोजन समिति के पदाधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराने की अपील की गई है। सभी व्यवस्था बेहतर तरीके से करने और

स्वयंसेवियों की मदद लेने पर भी जोर दिया गया है। डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह ने बताया कि साफ निर्देश हैं कि सभी जगहों पर प्रवेश और निकासी द्वार अलग-अलग हो, वालंटियर तैनात रहे, अग्निशमन उपकरण संबंधी मानक पूरे हों।

कार्यक्रम की अनुमति होने जैसी बातों का विशेष ध्यान रहे। वहीं पुलिस की ओर से त्योहारों पर पुलिस गश्त के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।

मोबाइल चोरी और छिन्नैती पर विशेष नजर पुलिस की ओर से कार्यक्रम के दौरान मोबाइल चोरी और छिन्नैती जैसी घटनाओं को रोकने पर विशेष जोर है। लोगों से भी अपील की गई है कि मोबाइल, पर्स, सोने की चीन जैसी कीमती चीजों का विशेष ध्यान रखें। घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

नवरात्र में बंद हों मांस-मदिरा की दुकानें सामाजिक एवं सनातनी आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर नवरात्र पर्व के दौरान नौ दिन तक मांस-मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। ये मांग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन व पुलिस आयुक्त से की है। जिलाध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कहा कि मंदिरों के आवागमन वाले मार्ग में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। यहां से आने-जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मतदान में लें बढ़-चढ़कर हिस्सा, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट; नहीं कटेगा छुट्टी का वेतन

प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग होगी है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों आदि में काम करने वाले सभी लोगों को छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

कोई भी विभाग किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटेगा। प्रदेश की सीमा से लगते दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी काम करने वाले प्रदेश के मतदाताओं को छुट्टी का भुगतान करना होगा।

क्या है जन प्रतिनिधि अधिनियम धारा 135बी के तहत

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार जन प्रतिनिधि अधिनियम धारा 135बी के तहत सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन काम करने वाले कामगारों के लिए छुट्टी का भुगतान करना होगा।

ताकि कामगार अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें। उन्होंने पात्र मतदाताओं से पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में बढ़-चढ़ कर मतदान करने का आह्वान किया है।

सभी औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन जिला की सीमा से लगते दिल्ली में स्थित उद्योगों को भी



वहां कार्यरत जिला फरीदाबाद के कर्मचारियों, जिनका जिला की मतदाता सूची में पंजीकृत है,

को भी सह वेतन अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में श्रम विभाग के अधिकारियों की

तरफ से सभी औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

हरियाणा में पिछड़ रही भाजपा मतदान से ठीक पहले मुश्किल स्थिति से कैसे उबर गयी?

निरज कुमार दुवे

इसमें कोई दो राय नहीं कि खट्टर से छुटकारा पाकर भाजपा ने हरियाणा में खट्टर को मुश्किल स्थिति से उबारने में सफलता पाई है। ऐसा लगता है कि यदि भाजपा ने मार्च में खट्टर को हटाने का फैसला नहीं लिया होता तो आज वह चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो चुकी होती।

हरियाणा में लगभग सवा नौ साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उपजी नाराजगी को भांप कर भाजपा नेतृत्व ने इस साल मार्च में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़वा कर और केंद्रीय मंत्री पद सौंप कर दिल्ली की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया गया लेकिन खट्टर का मन हरियाणा में लगा रहा। भाजपा नेतृत्व को जब यह लगा कि खट्टर का नाम नुकसान पहुंचा रहा है तो पूरे चुनाव प्रचार अभियान से खट्टर का नाम और उनकी तस्वीर गायब कर दी गयी। हमने पाया कि भाजपा की हर चुनावी रैली अथवा जनसभाओं के दौरान मंच पर या उसके आसपास लगने वाले पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंगों में खट्टर का नाम और तस्वीर नहीं थी। यही नहीं हरियाणा सरकार की जिन उपलब्धियों के सहारे भाजपा ने चुनाव लड़ा उसमें भी खट्टर की तस्वीर नहीं लगायी गयी। भाजपा ने साधारण लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार सामग्री में किया। जैसे युवाओं की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि बिना खर्ची पच्ची नौकरी दी गयी। किसानों की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि 24 फसलों का एमएसपी दे रही हरियाणा सरकार, महिलाओं की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि तमाम योजनाओं का लाभ दे रही भाजपा सरकार। इसी प्रकार अन्य उपलब्धियों का नाम दिया गया। भाजपा प्रचार सामग्री तैयार करवायी गयी जिसमें आम लोगों की तस्वीरें प्रकाशित की गयी थी।

ब्यूटी ब्लॉगर मालविका सीतलानी के तलाक के पीछे की वजह आई सामने

इसमें कोई दो राय नहीं कि खट्टर से छुटकारा पाकर भाजपा ने हरियाणा में खट्टर को मुश्किल स्थिति से उबारने में सफलता पाई है। ऐसा लगता है कि यदि भाजपा ने मार्च में खट्टर को हटाने का फैसला नहीं लिया होता तो आज वह चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो चुकी होती। खट्टर से व्यक्तिगत रूप से लोगों की नाराजगी भाजपा को चुनावों में उसी तरह नुकसान पहुंचा सकती थी जैसे कि राजस्थान विधानसभा के 2018 के चुनावों में देखने को मिला था जब नारे लग रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बसुंधरा तेरी खैर नहीं। हमसे बातचीत में भाजपा के भी कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने माना कि यदि खट्टर को हटाने का फैसला एक साल पहले लिया गया होता तो लोकसभा चुनावों में भी हम सारी सीटें जीत सकते थे।

इसके अलावा, 15 दिनों पहले जब हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की कवरेज की शुरुआत की थी उस समय सब जगह कांग्रेस की हवा ही दिख रही थी लेकिन एक दिन बीतने के साथ यह हवा हमें धीमी पड़ती दिखी और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो कहा जा सकता है कि हवा किसी एक पक्ष में नहीं है बल्कि कौंटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरियाणा चुनाव के दौरान मुझे दिल्ली नगरनिगम का पिछला चुनाव इसलिए याद आ गया क्योंकि उसमें भाजपा का सूपडा साफ होने की भविष्यवाणी की गई थी लेकिन जब परिणाम आये तो पार्टी नजदीकी मुकाबले में आम आदमी पार्टी से सिर्फ कुछ सीटों से पिछड़ गई थी। हरियाणा चुनावों में भी जमीनी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखी। ऐसा लगता है कि भाजपा को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह चुनाव में कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है तो उसने पिछले 10 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जनसभाएं कराई गयीं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुह मंत्री अमित



शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 70 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं कीं। जबामें भाजपा ने 150 सभाएं और रैलियां कर माहौल को पूरी तरह बदल दिया।

हरियाणा में कांग्रेस ने जमीनी तक इस बात को पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली थी कि 'कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है'। भाजपा ने इस हवा की चाल को धीमा करने के लिए परिवारवाद को मुद्दा बनाया और भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिछले शासन की याद दिलाई जिससे माहौल बदलने लगा।

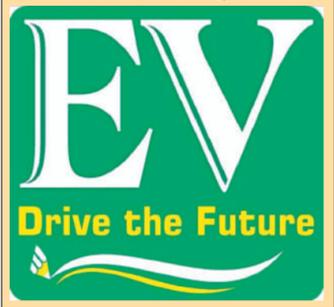
भाजपा ने जनता के बीच इस धारणा को मजबूत किया कि अगर कांग्रेस आई तो निश्चित रूप से हुड्डा को कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने भी बार-बार हुड्डा को ही कमान सौंपने के संकेत दिये जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होता दिखा क्योंकि हुड्डा को अपने पिछले कार्यकाल में सिर्फ रोहतक का सीएम माना जाता था और उन पर अपने आलाकमान को खुश रखने के लिए प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप भी हैं। कई क्षेत्रों के लोगों का मानना है कि हुड्डा ने सिर्फ रोहतक में काम किया जिससे वहां की जमीनों के रेट ज्यादा हैं और उनके इलाके की जमीनों का रेट बहुत कम है।

इसके अलावा भाजपा ने जिस एकजुटता और रणनीति के साथ हरियाणा में काम किया उससे पार्टी मुकाबले में तेजी से वापसी करती दिखी। रैलियों, सभाओं और डोर टूट्टर हुए प्रचार के बाद मिल रहे फीडबैक से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसलिए 3 अक्टूबर शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थमने तक भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री जनता के बीच लगातार पहुंचकर भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाने की अपील करते दिखे। भाजपा की रैलियों पर नजर डालें तो

पता चलता है कि पिछले लगभग एक महीने में प्रमुख नेताओं की 150 से अधिक जनसभाएं हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने रैलियों और रोड शो के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस को अनेक मुद्दों पर सफलतापूर्वक घेरा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने तो एक दिन में 4 से 5 बड़ी रैलियां कीं। भाजपा के लिए हरियाणा में सघन प्रचार करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आदि शामिल रहे। हरियाणा भर में कोई शहर या गांव ना छोड़े इसके लिए विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इ्यूट्टी भी लगायी गयी ताकि भाजपा की उपलब्धियों और पार्टी के संकल्प पत्र में किये गये वादों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने विपक्षी नेताओं और उम्मीदवारों के प्रचार और उनके संबोधनों पर बारीकी से निगाह रखी। यदि किसी विपक्षी नेता ने कोई विवादित बयान दिया तो उसको सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया।

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



खरीदिए इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी बदलने का खर्च नहीं पड़ेगा जब पर, वरना...बाद में मलते रह जाएंगे हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया और बैटरी शो इंडिया में बैटरी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 5 साल में सालाना 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। एक्सपो में इफॉर्मा माकेट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक

योगेश मुद्रास ने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024 और बैटरी शो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45 फीसदी कम करना है। एक्सपो में अक्षय ऊर्जा की दिशा में उठाए गए कदमों को दिखाया गया है। जैसे कुल 37.49 गीगावाट क्षमता वाले 50 सोलर पार्कों को मंजूरी, 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य और 2030 तक 30 गीगावाट पवन ऊर्जा हासिल करना।

फिलहाल देश में 1.6 करोड़ ईवी हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।



सिंपल एनर्जी अपने मोटर और बैटरी पर दे रही हैं 8 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ऊर्जा स्टार्ट-अप सिंपल एनर्जी ने अपने सिंपल प्रोटेक्ट और सिंपल सुपर प्रोटेक्ट बैटरी को कवर करता है, जबकि सिंपल सुपर प्रोटेक्ट बैटरी और मोटर दोनों को कवर करता है। इस पेशकश के साथ सिंपल एनर्जी भारत की पहली कंपनी बन गई है जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के साथ-साथ अपने मोटर पर 8 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी (जो भी पहले हो) प्रदान कर रही है।

सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वसनीयता को लेकर चिंताओं के कारण कई उपभोक्ता इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बारे में सतर्क रहते हैं। सिंपल एनर्जी ने अपनी बैटरियों को उनकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उन्नत थर्मल प्रबंधन, कंपन प्रतिरोध और रासायनिक इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया है। प्रत्येक बैटरी पैक कई सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, और कंपनी की पेटेंट मोटर तकनीक वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है।

कंपनी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने से उसे ऐसी बैटरी और मोटर बनाने में मदद मिली है जो बाजार में सबसे अलग हैं। डिजाइन, सामग्री चयन, सत्यापन परीक्षण और इन-हाउस विनिर्माण पर यह ध्यान उच्च गुणवत्ता वाले घटकों को सुनिश्चित करता है। ये प्रक्रियाएं विस्तारित वारंटी अर्थात् में योगदान करती हैं, जो संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों को



आश्वासन प्रदान करती है।

सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा, 'रहम उद्योगों ने अपने पेटेंट मोटर पर 8 साल की वारंटी देने वाले पहले निर्माता हैं, जो नवाचार और गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुसंधान और विकास में हमारे निवेश से हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मानकों को

बढ़ाने में मदद मिलती है। यह विस्तारित वारंटी उपभोक्ता की जरूरतों और अपेक्षाओं का जवाब है।

सिंपल एनर्जी वर्तमान में बंगलूर के राजाजीनगर, मराठाहल्ली और जेपी नगर जैसे स्थानों के साथ-साथ गोवा, विजयवाड़ा, पुणे और कोच्ची में सात स्टोर संचालित करती है। कंपनी अपने स्कूटर के

95% पुर्जे खुद बनाती है और तमिलनाडु के शूलागिरी में अपने 2,00,000 वर्ग फुट के फैक्ट में मोटर निर्माण लाइन संचालित करती है। सिंपल एनर्जी अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो संस्करण पेश करती है। एक 212 किमी की प्रमाणित रेंज के साथ और दूसरा 151 किमी की प्रमाणित रेंज के साथ।

खरीदिए इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी बदलने का खर्च नहीं पड़ेगा जब पर, वरना...बाद में मलते रह जाएंगे हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया और बैटरी शो इंडिया में बैटरी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत लिथियम-आयन बैटरी के स्वदेशी उत्पादन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उम्मीद है कि 2030 तक यह उत्पादन क्षमता 150 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो सेल की कुल मांग का 13 प्रतिशत कवर करेगी। बैटरी कंपनियों इसी तरह के लक्ष्य लेकर इस एक्सपो में पहुंची हैं। फिलहाल देश में 1.6 करोड़ ईवी हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्रा ई-बाइक्स हरियाणा के हिसार में 10 एकड़ से अधिक का विनिर्माण संयंत्र करेगी स्थापित

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता मंत्रा इंटरनेशनल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2025 में 40,000 से अधिक स्कूटर बेचने की योजना की घोषणा की है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कंपनी हरियाणा के हिसार में 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एक नई विनिर्माण

सुविधा खोलेंगी।

इस संयंत्र का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करना है। इस सुविधा में भारत में स्थायी परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने में मंत्रा ई-बाइक के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्वचालन प्रणाली को शामिल किया जाएगा।

2024 तक कंपनी 35,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री को पार कर चुकी है। 2023 में, मंत्रा ई-बाइक्स ने ई-रिक्शा कंपनी रिचलुक का अधिग्रहण करके अपने उत्पाद रेंज का विस्तार किया और हाइ-स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की एक लाइन पेश की। कंपनी का डीलरशिप नेटवर्क भी 2023 में 18 राज्यों तक फैल गया, जिससे पूरे भारत में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई।

संस्थापक दयानंद जैन ने कहा, 'हमारा मिशन सुरक्षा, प्रदर्शन और स्थिरता को मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन पेश करके गतिशीलता के भविष्य को नया आकार देना है।' उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रिक परिवहन को सुलभ, किफायती और सुविधाजनक बनाना है, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देना है।'

महिंद्रा ने अपने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जीयो इलेक्ट्रिक को किया लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की अग्रणी निर्माता कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल महिंद्रा जीयो लॉन्च किया है। शहरी लाइवस्टिक्स समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया जीयो दो वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 7.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू होती है।

जीयो, रेशून्स उत्सर्जन विकल्प रूप में संक्षिप्त है, जो परिवहन क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के प्रति महिंद्रा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। MLMMML, जो अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑफरिंग के लिए जानी जाती है, अब जीयो के साथ चार-पहिया स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में विस्तार कर रही है, जिसका लक्ष्य सब-2 टन श्रेणी को इलेक्ट्रिक बनाना है। कंपनी के अनुसार, पारंपरिक डीजल स्मॉल कमर्शियल व्हीकल की तुलना में उपयोगकर्ता सात वर्षों में ₹7 लाख तक बचा सकते हैं।

जीयो एक उच्च-वोल्टेज 300+ V आर्किटेक्चर द्वारा संचालित है, जो ऊर्जा दक्षता, रेंज और चार्जिंग गति को बढ़ाता है। इसकी उन्नत इलेक्ट्रिक मोटर 30 kW की शक्ति और 114 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है, जबकि 21.3 kWh की लिक्विड-कूल्ड बैटरी मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। वाहन की अधिकतम गति 60 किमी/घंटा है और इसकी पेलोड

क्षमता 765 किलोग्राम तक है, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा 2,250 मिमी का कार्गो बॉक्स है।

रेंज के मामले में, जीयो रीजनल ट्रेकिंग तकनीक द्वारा समर्थित 160 किमी तक की वास्तविक ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है। एक डीसी फास्ट चार्जर केवल 60 मिनट में 100 किमी की रेंज प्रदान करता है, और वाहन विभिन्न चार्जिंग कॉन्फिगरेशन के साथ उपलब्ध है, जिसमें मानक के रूप में 3.3 किलोवाट ऑनबोर्ड चार्जर शामिल है।

जीयो की 32% ग्रेडेबिलिटी इसे खड़ी चढ़ाई से निपटने के लिए उपयुक्त बनाती है, जो 2 टन से कम वजन वाले इलेक्ट्रिक कार्गो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसका ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और फ्रंट फंक्शन ड्राइवर की थकान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में। 4.3 मीटर के कम टर्निंग रेडियस के साथ, जीयो संकीर्ण शहर की सड़कों पर भी बेहतर गतिशीलता प्रदान करता है। अंदर, केबिन में डैशबोर्ड-माउंटेड ट्रांसमिशन डायल, टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग स्लॉट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे व्यावहारिक सुविधाएँ हैं।

वाहन को महिंद्रा के NEMO टेलीमैटिक्स सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे फ्लोटी मैनेजर और व्यक्तिगत ड्राइवर वास्तविक समय के डेटा तक पहुंच सकते हैं। फ्लोटी मैनेजर



प्रदर्शन, जियोफेंस स्थानों की निगरानी कर सकते हैं और सेवाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, जबकि ड्राइवर NEMO ऐप के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग हब, सर्विस लोकेटर और ट्रिप प्लानर तक पहुंच सकते हैं।

जीयो सात साल या 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी के साथ आता है। इसके अलावा, महिंद्रा सफर और सफर प्लान के तहत दो सर्विस पैकेज दे रहा है, जिसमें रोडसाइड अडिस्टेंस, एक्सप्रेस सर्विस और एक्सप्रेट डेड वारंटी विकल्प शामिल हैं।

जीयो के डिजाइन में सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह एडवांस्ड

ड्राइवर अडिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए AI-सक्षम कैमरे से लैस है, जो लेन प्रस्थान चेतावनी, पैदल यात्री टक्कर अलर्ट और ड्राइवर व्यवहार विश्लेषण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। जीयो में हिल होल्ड अडिस्टेंस भी शामिल है, जो ढलान पर स्थिरता सुनिश्चित करता है, और बैटरी और मोटर पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67 मानकों को पूरा करते हैं।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री सुमन मिश्रा ने छोटे वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए जीयो की क्षमता पर भरोसा

जाता है। उन्होंने वाहन को अंतिम मील परिस्थितियों तक को फिर से परिभाषित करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के कंपनी के सिद्धांत का प्रमाण बताया।

यह लॉन्च इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में महिंद्रा के निरंतर विस्तार का संकेत देता है, और जीयो का लक्ष्य 2 टन से कम क्षमता वाले इलेक्ट्रिक सेगमेंट में गेम-चेंजर बनाना है।

महिंद्रा जीयो दो डेक प्रकारों में उपलब्ध है- फ्लैट साइड डेक (FSD) और डिलीवरी वैन (DV)। FSD वैरिएंट की कीमत V1 वर्शन के लिए ₹7.52 लाख से शुरू होती है, जबकि V2 की

कीमत ₹7.69 लाख है। डिलीवरी वैन मॉडल की कीमत V1 के लिए ₹7.82 लाख और V2 वैरिएंट के लिए ₹7.99 लाख है।

महिंद्रा जीयो में दो क्षमता विकल्पों के साथ लिथियम आधारन फॉस्फेट (LFP) बेलनाकार बैटरी है। V1 वैरिएंट 18.4 kWh बैटरी के साथ आते हैं, जबकि V2 मॉडल में 21.3 kWh क्षमता है। दोनों मॉडल 30 kW का अधिकतम पावर आउटपुट और 114 Nm का पीक टॉर्क देते हैं, जिसमें निरंतर टॉर्क 60 Nm पर रेट किया गया है। वाहन एक उच्च-वोल्टेज प्रणाली पर संचालित होता है, जिसमें V1 मॉडल 307 V और V2 मॉडल 355 V

पर चलते हैं।

60 किमी/घंटा की अधिकतम गति और 32% की अधिकतम ग्रेडेबिलिटी के साथ, महिंद्रा जीयो को शहर और अर्ध-शहरी सड़क स्थितियों को आसानी से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दो ड्राइविंग मोड प्रदान करता है - इको और पावर - साथ ही बेहतर ड्राइवबिलिटी के लिए हिल होल्ड अडिस्टेंस और क्रैप फंक्शन जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

जीयो सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन से भी लैस है और बेहतर स्थिरता और आराम के लिए मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन के साथ सेमी ट्रेलिंग आर्म रियर सस्पेंशन का उपयोग करता है।

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में चल रहे अवैध चार्जिंग स्टेशनों पर करेगी कार्रवाई

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल में कहा-कहा अवैध चार्जिंग स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। कहा-कहा पर ई-वाहन, ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे स्टेशनों का पता लगाकर बिजली कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को संधन चेंकिंग कर सात दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

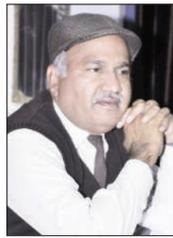
कंपनी ने बताया कि ई-वाहन, ई-रिक्शा आदि की चार्जिंग के लिए बिजली का लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इन वाहनों के मालिकों की जानकारी कंपनी के संज्ञान में आई है।

इस वजह से मैदानी अधिकारियों से जांच करने के लिए कहा है। जांच के दौरान यदि अवैध चार्जिंग होना पाया जाता है तो उपकरण व वाहन को जब्त किया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिजली अधिकारियों के द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जांच में मीटर क्रमांक, उसकी कार्य प्रणाली एवं श्रेणी दर्ज किया जाएगा। ई-वाहनों के मालिकों की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त कर उनके बिजली कनेक्शन को एनजीबी (नेक्स्ट जनरेशन बिलिंग) प्रणाली में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।



शैक्षणिक संस्थान छात्रों को डिजिटल उपकरणों से अलग होने में कैसे मदद कर सकते हैं



विजय गर्ग

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि, माध्यमिक छात्रों के लिए, महत्वपूर्ण सीखने के अनुभव - एकाग्रता, जुड़ाव, अवधारणाओं को समझने की क्षमता और यहां तक कि शिक्षार्थी के रूप में आत्म-मूल्य - को तब काफी नुकसान हुआ जब कक्षाएं भौतिक कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन आयोजित की गईं। अनगिनत छात्र ध्यान भटकाने वाले उपकरणों से जुड़ रहे हैं, मनोरंजन, सोशल मीडिया और यहां तक कि शैक्षणिक ऐप्स की निरंतर खींच से खुद को अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

छात्र तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में नेविगेट कर रहे हैं, शिक्षक उन्हें डिजिटल से अलग होने और वास्तविक दुनिया से फिर से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। छात्रों को उपकरणों से अलग होने का अवसर देते हुए संयम के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। 2023 के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अध्ययन के अनुसार, आज युवा अपने विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान स्क्रीन पर अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक वयस्कता में प्रवेश करते समय हल्के संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। इससे भी बदतर, अध्ययन का अनुमान है कि इससे बाद के चरण में प्रारंभिक-शुरुआत मनोभ्रंश की दर में वृद्धि होगी। जबकि स्वास्थ्य अधिकारी वर्तमान में दो गुना वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, इस अध्ययन में मनोभ्रंश दरों में संभावित चार से छह गुना वृद्धि की उम्मीद है। लेकिन यह प्रक्षेपण एक पृष्ठ पर आंकड़ों से कहीं अधिक है। यह आज के किशोरों के डिजिटल व्यवहार में सन्निहित है। किसी भी दिन, औसत किशोर खुद को औसतन छह घंटे तक स्मार्टफोन या डिजिटल डिवाइस से बंधा हुआ पाता है। इसका असर देश भर के शिक्षण संस्थानों पर दिखने लगा है। शिक्षकों और छात्र समर्थकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता सीखने की नौव को कैसे कमजोर कर सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि, माध्यमिक छात्रों के लिए, महत्वपूर्ण सीखने के अनुभव - एकाग्रता, जुड़ाव, अवधारणाओं को समझने की क्षमता और यहां तक कि शिक्षार्थी के रूप में आत्म-मूल्य - को तब काफी नुकसान हुआ जब कक्षाएं भौतिक कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन आयोजित की गईं। अनगिनत छात्र ध्यान



भटकाने वाले उपकरणों से जुड़ रहे हैं, मनोरंजन, सोशल मीडिया और यहां तक कि शैक्षणिक ऐप्स की निरंतर खींच से खुद को अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उठाने के लिए कदम इस डिजिटल गडबडी में, शैक्षणिक संस्थान भौतिक दुनिया के साथ वास्तविक वियोग और सार्थक पुनः जुड़ाव का मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञ रूप से तैयार हैं। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे संस्थान अपने छात्रों की मदद कर सकते हैं। कई उपायों में से, सबसे शक्तिशाली उपाय शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भीतर खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह न केवल स्क्रीन से बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है, बल्कि समग्र कल्याण के लिए कई लाभ भी प्रदान करता है। यह सभी कक्षाओं के लिए दैनिक शारीरिक शिक्षा या गतिविधि अवधि को अनिवार्य करके किया जा सकता है, अंतर-कक्षा प्रतियोगिताओं के माध्यम से

खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना; योग और ध्यान जैसी सचेतन प्रथाओं को दैनिक समय सांख्यिकी में एकीकृत करना; और पुराने खेल के मैदानों को फिटनेस हब में बदलना जो सक्रिय जीवनशैली की वकालत और प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा, शिक्षाविदों के बाहर छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनका जश्न मनाया जाना चाहिए। छात्रों को प्रेरित करने के लिए रोल मॉडल और स्वस्थ जीवन शैली के राजदूतों को बातचीत के लिए आमंत्रित करना एक और कदम है। बाहरी पहल जैसे लंबी पैदल यात्रा, सिविल, पर्यावरण प्रबंधन और बहुत कुछ विभिन्न कार्यक्रमों और यहां तक कि शैक्षणिक संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह सब युवाओं को टीम वर्क, अनुशासन और सामाजिक संपर्क जैसे अमूल्य जीवन कौशल विकसित करने में मदद करेगा और उन्हें एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण रूप से,

शारीरिक परिश्रम दबी हुई ऊर्जा को मुक्त करने की अनुमति देता है और अत्यधिक डिजिटल उत्तेजा से बड़े हुए तनाव के स्तर को कम करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम से फोकस और एकाग्रता बढ़ती है और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है। जैसाछात्र तेजी से बढ़ती आभासी दुनिया में घूम रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों को एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। छात्रों को संयम के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें उपकरणों से अलग होने और भौतिक दुनिया के साथ फिर से जुड़ने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक संतुलित जमीन वाले व्यक्तियों की एक पीढ़ी बनाने में मदद कर सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से जीवंत जीवन जीते हुए शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कोर चंदा एमएचआर मलोट पंजाब

संपादक की कलम से

बार-बार पैरोल

डेटा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर आया है। हरियाणा चुनाव के मतदान से एेन पहले उसे 20 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया है। चार साल में 15वीं बार उसे पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला है। न कोई आपातस्थिति है, न कोई आकस्मिकता है और न ही कोई मरणान्त है, लेकिन किसी 'फैमिली मैटर' के आधार पर पैरोल दी गई है। वह पारिवारिक मामला क्या है? क्या बाबाओं का भी पारिवारिक मामला होता है? बेशक छद्म ही सही, राम रहीम लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूज्य हैं, आस्था का पात्र हैं, लेकिन वह नाबालिंग साध्वियों के साथ बलात्कार और एक पत्निकार की हत्या करीब 15 घण्टी अपराधों में सजायापता है। उसे एक मामले में 20 लंबे साल और अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेशक पैरोल एक सजायापता कैदी का स्थितिजन्य अधिकार है और फरलो को जेल के दस्तावेजों और नियमों में 'इनाम' करार दिया गया है। जब भी पुलिस और जेल सुधारों का उल्लेख होता है, तो उनमें कैदी को ज्यदा से ज्यदा जेल के बाहर रखना 'सुधारात्मक' माना गया है। उससे कैदी के व्यवहार और मानसिकता में सुधार होगा और वह ज्यदा सामाजिक होगा। उन सुधारों में ही 'फरलो' को एक इनाम माना गया है, जो जेल प्रशासन एक कैदी को दे सकता है। हालांकि अलग-अलग राज्य में फरलो की अवधि तय है। फरलो का ही विकल्प पैरोल है। बहरहाल यह संयोग है या कोई प्रयोग है कि राम रहीम को लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका या पंचायत चुनावों के दौरान ही पैरोल या फरलो दी जाती रही है। बेशक वह एक प्रभावशाली शख्स है और

आधुनिक युग में रामलीला की प्रासंगिकता

राय भरोसे की की दुनिया

पिछले कुछ समय से आपसपास कहीं गुंजाता में 'एक गीत 'पाप की परी' बहुत सारी लड़कियों के कान में भी गया होगा। मगर यह सुनते हुए लड़कियों के मन में क्या कही यह खाल भी खड़ा होता है कि लड़कियों को परी क्यों कह दिया गया ? क्या लड़कियां सपनों की तरह होती हैं, बस एक मासूम सा चेहरा, जो हमेशा मुस्कुराती रहे ? क्यों लड़के परी के समांतर कुछ और नहीं कहे जाते ? क्यों बड़े नाज से पालते हुए लड़कियों को हर वक़्त अहसास दिलाया जाता है कि वे कमजोर हैं और कोई भी उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है ? क्यों उनके लिबास पर तंज कसे जाते हैं और क्यों इतनी रोकटोक लगाई जाती है ? ये सवाल किसी एक लड़की के नहीं होंगे, बल्कि आज इस तरह के जवाब की मांग उठ चुकी है कि क्यों अपने घर के लड़कों को समानता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता ! क्यों उन्हें नहीं समझाया जाता कि लड़की भी एक इंसान है, उसे भी हक है बेटों की तरह बराबरी से जीने का... अपनी सुविधा और इच्छा से पहनने और घूमने का सोच बदलने की जरूरत लड़के की है, जिसके नजरिए से लड़की बस कमजोर, अहसाय काया जान पड़ती है।

आए दिन महिलाओं के खिलाफ रहे जघन्य अपराध सूक्त हैं इस बात के कि बदलाव बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी है समझना कि अपराधियों को दुरिंदगी महज कुछ घंटों की उपज नहीं है, बल्कि हर गली, हर मोड़ पर, घर, कार्यस्थल, स्कूल-कालेज में हर जगह जाने कितनी बार ऐसी अपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने महिलाओं के बारे में क्या-क्या सोचा होगा, क्या रया बनाई होगी। बलाकार तो आहिंसा चर्चा भी करते हैं, अपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कायम महिलाओं के खिलाफ अपराधिक सोच अपराध की शुरुआती बुनियाद है। जब-जब बलात्कार की कोई वीभत्स घटना होती है, तब जनता साथ खड़ी होकर आंदोलन करती है। हर जगह आवाज उठाई जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला फिर शांत हो जाता है। इससे ऐसी अपराधिक प्रवृति वाले लोग और ज्यदा बेलागम हो जाते हैं।

दिल्ली में एक समय 'निर्भया कांड' ने देश भर में लोगों को झकझोर दिया था। तब काफी आंदोलन हुए थे, लेकिन सुरक्ष के नाम पर आज तक शून्य मिल रहा है। आज भी आए दिन महिलाओं के खिलाफ बलात्कार से लेकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों को जन्म दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना को संज्ञान में आ सक्ती, वरना हर उम्र पता नहीं कितनी घटनाएं कैसे होती हैं और दर्पण हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकतीं। अतीत से लेकर आज तक के तमाम उदाहरण पर भेड़ हैं, जिनमें लड़कियों जीवन से लेकर हर क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। आज भी वे रिहा कर सकती हैं, बस यह सोचने की जरूरत है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। उन्हें अपना भरोसा खुद ही अर्जित करना है और खुद ही अपनी ताकत बननी है। आज जरूरी हो गया है कि कुछ ठोस पहलकदमी हो, जिससे न केवल अपराधों का सिलसिला धैमे, बल्कि अपराधों की जड़ यानी लोगों की सोच में बदलाव हो। यह जागरूकता अभियान सिर्फ स्कूल-कालेजों के पाठ्यक्रम के मौजूदा स्वरूप तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसके लिए शिक्षा के बीच से लेकर समाज के स्तर पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की जरूरत है। वैसी शिक्षा जरूरी है बच्चों के माता-पिता को यह समझाने के लिए कि लड़का या लड़की, पालने से लेकर बच्चों के साथ बर्ताव तक के हर मामले में लैंगिक भेदाभाव परंपरे दिया जाए और अपने बेटों को प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने का पाठ पढ़ाया जाए।

हर बार लाचारी का ठीकरा लड़कियों के सिर फोड़ने के बजाय सबके भीतर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के विकास के लक्ष्य से सामाजिक प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके समांतर वैसी लड़कियों को इस स्वरूप में शिक्षा मिले, जो सोचनी है कि भौतिक संघर्ष नहीं कर सकतीं। जब लड़की अपनी जान पर खेल कर ऐसे लड़कों को जन्म दे सकती है तो वह सब कर सकती है, जो उसके अपने और स्त्री के अस्तित्व के लिए जरूरी है। सबसे पहले और सबसे ज्यदा जरूरत है। अपने भीतर आत्मनिश्चय जगाने की और यह सब कुछ मुमकिन करने के लिए खुद पर भरोसा करने की, जिसे करना नामुमकिन माना जाता रहा है। आज की दुनिया में लड़कियों को जैसे त्रासदी का सामना करना पड़ता है, उसमें उन्हें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि उन्हें 'पाप की परी' कह कर संभावित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी के युग में पालन-पोषण की चुनौतियाँ : विजय गर्ग

हालाँकि चुनौतियाँ वास्तविक हैं, इसलिए समाधान भी हैं - अनुकूलन और धैर्य इस डिजिटल समय में सफल पालन-पोषण की आधारशिला बने हुए हैं इन दिनों बातचीत इस बात पर जोर देती है कि जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है और अशांत समुद्र में सँफ़िण करणा उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। मुझे आश्चर्य होता है कि आधुनिक दुनिया ने हमें जो सुविधाएं प्रदान की हैं, उसके बावजूद हम इस दृष्टिकोण का आसानी से समर्थन करते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सर्वोपरि सुधार ने हमें उस संतुष्टि की भावा लाने के मामले में कुछ खास नहीं किया है जो भौतिक संघर्ष लाने वाला माना जाता है। इसके बजाय, हम केवल अधिक पागल और अधिक शिकायती बन गये हैं। जिन चीजों को लेकर हम शिकायत करते हैं, उनमें से एक चीज सबसे खास है - इस समय में माता-पिता बनने की कठिनाई। ऐसा नहीं है कि यह तब होता था जब हम बच्चे थे, वे दावा करते हैं और आज

रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों और दर्शकों की आराध्य देव के प्रति आस्था और समर्पण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित होता है। यह समर्पण उनके व्यक्तित्व को निखारता है, उन्हें एक नई दिशा भी देता है।

देवभूमि में रामलीला और रामायण देव-परम्परा देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सबसे मूलभूत और सशक्त पहचान रही है। हमारे दैनिक जीवन, परम्पराओं, रीति-रिवाजों और जीवन मूल्यों पर देवी-देवताओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं, इन देवी-देवताओं की आस्था का अभिकेन्द्र भगवान रघुनाथ (भगवान श्रीराम) रहे हैं। जिस प्रकार से हिमाचली समाज देवी-देवताओं की आराधना करता है, उसी प्रकार से हमारे देवी-देवता भगवान रघुनाथ को अपना आराध्य देव मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशरथा में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देवी-देवता भगवान रघुनाथ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हैं। इस अवसर पर हर वर्ष भगवान रघुनाथ की एक वृष शोभायात्रा निकाली जाती है। सभी देवता इसमें उपस्थित होकर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सम्भवतः इसी कारण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रामलीला मंचन को लेकर विशेष आस्था और आकर्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार, देव परम्परा के केंद्र में स्थित भगवान राम हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रमुख आधार है और उनके प्रति समर्पण रामलीला जैसे आयोजनों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तीन अक्टूबर से



शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कस्बों और गांवों में रामलीला का मंचन भी प्रारम्भ होगा। इसमें भगवान श्रीराम की जीवन यात्रा का नाटकीय रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रामलीला में स्थानीय कलाकार पारम्परिक वेशभूषा धारण करके रामायण के पात्रों को जीवंत करते हैं। इस लोक नाट्य रूप में मंचित रामलीला में गीत, संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से भगवान राम की कथा का मंचन किया जाता है। यह रामलीला लोगों को भगवान राम के आदर्श जीवन की स्मृति दिलाती है और समाज को धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देती है। इससे समाज में आशीर्वाद और धार्मिकता को बल मिलता है। इस प्रकार रामलीला का मंचन हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सजावर रखता है और देव समाज की धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करता है। हिमाचल प्रदेश में रामलीला का मंचन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता का

भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। रामलीला की विशेषता यह है कि इसमें हर जाति, मत और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। विभिन्न समुदायों से आने वाले लोग एक क्लब या सहज में शामिल होकर रामायण की कथा का सामूहिक मंचन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदाभाव या सामाजिक असमानता नहीं होती, बल्कि सभी समान रूप से भगवान राम के आदर्शों और रामायण की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए सहयोग करते हैं। इससे सामाजिक भेदाभाव को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होता है। यह प्रक्रिया समाज में समानता और सहिष्णुता को प्रकट करती है, जिसमें सब लोग धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और सम्पर्ण को साझा करते हैं। इससे समाज में एकत्र होकर सांस्कृतिक आस्था का संदेश प्रसारित होता है। इस प्रकार रामलीला हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है, जो पूरे समाज को एकजुट रखने में सहायक है।

रामलीला मंचन भारतीय संचार परम्परा की एक अनूठी एवं प्रभावशाली परम्परा है। मध्यकाल से ही भारत में रामलीला का मंचन होता आ रहा है। इसके बावजूद दर्शकों में इसके प्रति आकर्षण कभी कम नहीं हुआ है। हर वर्ष रामलीला मंचन की विषयवस्तु एक ही रहती है। दर्शकों को मालूम होता है कि किस समय कौनसा दृश्य आएगा। हर साल इसका कथक और घटनाक्रम समान रहता है, फिर भी यह हर बार दर्शकों के लिए नई प्रेरणा और अनुभव लेकर आता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार भारतीय संचार परम्पराएं स्थायित्व और एकत्र होने के साथ पुनरावृत्ति में भी प्रभावी होती हैं। इस प्रकार रामलीला केवल धार्मिक नाटक भर नहीं है, बल्कि यह संवाद का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग एकत्र होकर सांस्कृतिक अनुभव साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रामलीला मंचन की परम्परा निरंतर समृद्ध होती जा रही है। हर वर्ष नए क्लब खड़े हो रहे हैं। खास बात यह कि ये रामलीला क्लब और कार्यक्रम बिना किसी

सरकारी प्रश्रय के आगे बढ़ रहे हैं। समाज ही इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए संसाधनों की व्यवस्था करता है। सामाजिक सहयोग के बलवृत्ति ही यह आयोजन निरंतर बढ़ रहे हैं। हालाँकि पिछले कुछ समय कुछ स्थानों पर इन मंचों पर अश्लीलता को भी स्थान मिलने लगा था। मगर समाज के उचित दखल और इस मंच की मर्यादों को समझते हुए इस कुप्रथा पर विराम लगा है। यह एक सुखद संकेत है। रामलीला मंचन करने वाले कलाकार और देखने के लिए आने वाले दर्शक अपने आराध्य देव के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण भाव लेकर आते हैं। इसलिए नशाखोरी जैसी बुराईयों को समाप्त करने से लेकर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दृष्टि से रामलीला का मंचन अत्यंत उपयोगी रहा है। अतः हिमाचल प्रदेश में जब पिछले कुछ समय से नशाखोरी की आदत बढ़ने लगी है, रामलीला से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर नशामुक्त समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों और दर्शकों की आराध्य देव के प्रति आस्था और समर्पण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक साबित होता है। यह समर्पण न केवल उनके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि उन्हें एक नई दिशा देने में भी मदद करता है। क्लब का कोई सदस्य अगर नशाखोरी की चपेट में आ भी गया हो, तो रिहांसल शुरू होने से लेकर दशरथा तक वह इससे मुक्ति पा सकता है। इससे प्रभाव में कई युवाओं ने हमेशा-हमेशा के लिए नशा छोड़कर बेहतर जीवन जीना शुरू किया है। हिमाचल में नशाखोरी की समस्या के प्रचलन के मद्देन देखते हैं, रामलीला मंचन युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। रामलीला को प्रासंगिकता यही है।

डॉ. रविंद्र सिंह

प्रौद्योगिकी के युग में पालन-पोषण की चुनौतियाँ : विजय गर्ग

बच्चों को नियंत्रण में रखने में असमर्थ हैं, चाहे वह गैजेट के उपयोग के बारे में हो या नए जमाने की सुख-सुविधाओं के लिए उनकी मांगों के बारे में हो या अच्छी सलाह का पालन करने के बारे में हो। आजकल बच्चों के बड़े होने का तरीका ऐसा होता है कि माता-पिता उस पर पकड़ नहीं बना पाते, और माता-पिता अपनी बुद्धि के अंत में होते हैं। क्या पालन-पोषण अब इतना कठिन हो गया है, हमारे माता-पिता या उनके माता-पिता के लिए पहले की तुलना में अधिक कठिन ? इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि अब यह पहले से कहीं अधिक कठिन क्यों लगता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पालन-पोषण हमेशा से कठिन रहा है। हमारे दादा-दादी को भले ही सोशल मीडिया की लत या लगातार सतक रहने की चिंता से नहीं जुड़ना पड़ा हो, लेकिन उनकी अपनी चिंताएं थीं - कमी, जानकारी की कमी और कम अवसर। फिर भी, वे कामयाब रहे, जैसे हम आज प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं। तो

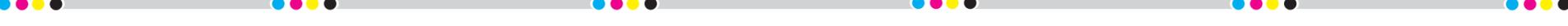
फिर, इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ है कि माता-पिता अब लगभग निरंतर निराशा का भाव महसूस करते हैं ? उदाहरण के लिए, डिजिटल युग ने न केवल हमारे जीने के तरीके को बल्कि बच्चों के पालन-पोषण के तरीके को भी बदल दिया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, वीडियो गेम - ये सभी ध्यान भटकाने वाले सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं, वे बच्चों के सोचने, कार्य करने और यहां तक कि वास्तविकता को समझने के तरीके को आकार देते हैं। माता-पिता अक्सर इस डिजिटल हमले के सामने शक्तिहीन महसूस करते हैं, वे अनिश्चित होते हैं कि सत्तावादी या अपने 'फ्लैगला' को कहाँ भी बनाना का दबाव कुचलने की वलाही बनती है। बच्चों को 'अच्छा' बनाने के हमारे दादा-दादी के विचार को 'अचौंस' बनाने की आवश्यकता से बदल दिया गया है, और फोकस में यह बदलाव माता-पिता को ऐसा महसूस करा सकता है जैसे वे बिना किसी फिनिश लाइन के दौड़ में भाग ले रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, पालन-पोषण कोई हारा हुआ कारण

दबाव का मुद्दा है। 'इंस्टाग्राम-परफेक्ट' जीवन पालन-पोषण में तनाव की एक प्रतीक जोड़ता है जिसका पिछली पीढ़ियों को सामना नहीं करना पड़ा। आज माता-पिता न केवल अपने पालन-पोषण का सर्वोत्तम संस्करण बनने के लिए स्वयं से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं - वे पूर्णता के उस क्यूरेटेड संस्करण के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिसे वे ऑनलाइन देखते हैं। बच्चों को पाठ्येतर गतिविधियों में नामांकित करने, यह सुनिश्चित करने कि उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है, नेतृत्व कौशल विकसित करने और भविष्य की सफलता को कहाँ भी बनाने का दबाव कुचलने की वलाही बनती है। बच्चों को 'अच्छा' बनाने के हमारे दादा-दादी के विचार को 'अचौंस' बनाने की आवश्यकता से बदल दिया गया है, और फोकस में यह बदलाव माता-पिता को ऐसा महसूस करा सकता है जैसे वे बिना किसी फिनिश लाइन के दौड़ में भाग ले रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, पालन-पोषण कोई हारा हुआ कारण

नहीं है। यह परीक्षण और जूटि की यात्रा है और हमेशा रहेगी। कुंजी संतुलन ढूँढना और यह जानना है कि पूर्णता न तो प्राप्य है और न ही आवश्यक है। शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह अपने बच्चों के साथ मजबूत संबंध बनाना है। माता-पिता को भी ऐसा स्वीकार करना होगा कि वे ऐसा नहीं कर सकतेसारी लड़ाई अकेले लड़ो। उन्हें मदद मांगनी चाहिए, आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें से कई नई और अपरिचित हैं, लेकिन



इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुर्गम हैं। जिस तरह पिछली पीढ़ियों ने अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढा, उसी तरह हम भी ढूँढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूलन, सीखने और, सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य की आवश्यकता होगी। आखिरकार, हमारे बच्चे केवल अपने पर्यावरण के उपाद नहीं हैं - वे उस प्यार, समर्थन और ज्ञान का प्रतिबिंब हैं जो हम उन्हें देते हैं, चाहे उनके आपसपास की दुनिया कितनी भी तेजी से क्यों न बदल।



पांच सत्रों में चार हजार अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स, सोमवार को कैसा रहेगा माहौल ?

परिवहन विशेष न्यूज़

भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई सेंसेक्स तीन सप्ताह के निचले स्तर 81688 पर आ गया है। हालांकि निफ्टी 25 हजार के पार बंद होने में कामयाब रहा। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति 16.26 लाख करोड़ रुपये घट गई है। आइए जानते हैं कि अगले हफ्ते बाजार का मिजाज कैसा रहेगा।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण जारी बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों में बीते पांच दिनों से लगातार गिरावट जारी है। इन पांच सत्रों में बीएसई प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 4,147.67 अंक लुढ़ककर 82 हजार से नीच आ गया है। इसी प्रकार, एनएसई का निफ्टी 1,201.45 अंक लुढ़क चुका है। हालांकि, यह अभी 25 हजार से ऊपर बना हुआ है।

इन पांच सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में 16.26 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है और अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 460.89 लाख करोड़ रुपये या 5.49 ट्रिलियन डालर रह गया है।

शुक्रवार को भी मार्केट लहलहा न
एफएमसीजी, आटो और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के चलते शुक्रवार को सेंसेक्स भारी उतार-चढ़ाव के बीच 808.65 अंक की गिरावट के साथ तीन सप्ताह के निचले स्तर 81,688.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 81,532.45 के निचले स्तर और 83,368.32 के उच्च स्तर तक पहुंचा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 1,835.64 का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 235.50 अंक गिरकर 25,014.60 पर बंद हुआ। कारोबार के

पेटीएम ने शुरू किया यात्रा कार्निवल, फ्लाइट के साथ सस्ते में मिल रही ट्रेन टिकट

फेस्टिव सीजन से पहले फिनेट कंपनी Paytm ने Travel Carnival लॉन्च किया है। Travel Carnival में यूजर डिस्काउंट के साथ फ्लाइट टिकट और बस की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम के पार्टनरशिप बैंक के जरिये बुकिंग करने पर अतिरिक्त लाभ भी पा सकते हैं। पेटीएम ने इसके लिए प्रोमोकोड भी जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर...



नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में पेटीएम (Paytm) ने अपने यूजर को लाभ देने के लिए Travel Carnival शुरू किया है। इस Carnival में यूजर सस्ते दर पर फ्लाइट टिकट के साथ ट्रेन और बस टिकट भी मिल रही है। यह फेस्टिवल 26 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर तक रहेगा। इसका मतलब है कि यूजर इस बीच तक सस्ती दर पर टिकट बुकिंग कर सकते हैं।

Paytm Travel Carnival ऑफर
● Paytm के Travel Carnival में यूजर फ्लाइट टिकट पर 5,000 रुपये तक बचा सकता है।
● वहीं बस और ट्रेन की टिकट पर 25 फीसदी तक का ऑफ मिल रहा है।
● पेटीएम ने प्री कैंसिलेशन की सुविधा भी दी है। इसका मतलब है कि फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट को कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
● पेटीएम ने अपने बैंक पार्टनरशिप के साथ भी कई ऑफर लाया है। ICICI Bank, RBL Bank, Bank of Baroda, और AU Small Finance

किसानों के खाते में आंगे 20 हजार करोड़, PM मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त



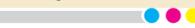
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसमें तीन बराबर किस्तों में भूमिधारक किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं। 18वीं किस्त के तहत कुल 3.45 लाख करोड़ से अधिक राशि पात्र किसानों के खाते में चली जाएगी। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब जारी होगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18वीं किस्त को शनिवार को आंगे। प्रत्यक्ष अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा। पीएम

मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसमें तीन बराबर किस्तों में भूमिधारक किसानों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाते हैं। 18वीं किस्त के तहत कुल 3.45 लाख करोड़ से अधिक राशि पात्र किसानों के खाते में चली जाएगी।

कैसे मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ
पीएम किसान योजना की सभी किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती है। इसका मतलब है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी बिचौलिये से संपर्क करने की जरूरत नहीं। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको लाभार्थियों की लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। इससे कन्फर्म हो जाएगा कि

आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं और समय रहते गड़बड़ी को दूर भी करवा सकेंगे।
लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट (<https://pmkisan.gov.in/>) पर जाएं। यहां जाकर farmer corner के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए।
न्यू पेज ओपन होगा। इसमें beneficiary list पर क्लिक करें। राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम सेलेक्ट करें।
इसके बाद get report पर क्लिक कीजिए।
अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट आपन होगा। इस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा। अगर नाम होता है तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर नाम नहीं है, तो आप जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।



सब्जियों ने बिगाड़ा शाकाहारी थाली का जायका, सितंबर में 11 फीसदी बढ़ा भाव



रेटिंग एजेंसी ने रोटी राइस रेट रिपोर्ट में थाली की लागत में वृद्धि के लिए सब्जियों के मूल्य में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। थाली की कुल लागत में सब्जियों की 37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में प्याज आलू तथा टमाटर की कीमतें क्रमशः 53, 50 और 18 प्रतिशत बढ़ीं। वहीं सितंबर में मांसाहारी थाली सस्ती हुई है।

नई दिल्ली। महंगे प्याज, आलू और टमाटर के कारण सितंबर में घर पर बनाए जाने वाले शाकाहारी खाने की लागत में बढ़ोतरी रही है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने घर पर बनाई जाने वाली शाकाहारी थाली की लागत 31.3 रुपये रही है। यह सितंबर 2023 की लागत 28.1 रुपये से 11 प्रतिशत अधिक है। इसी वर्ष अगस्त की 31.2 रुपये के मुकाबले भी पिछले महीने शाकाहारी थाली की लागत बढ़ी है।

रेटिंग एजेंसी ने 'रोटी, राइस, रेट' रिपोर्ट में थाली की लागत में वृद्धि के लिए सब्जियों के मूल्य में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। थाली की कुल लागत में सब्जियों की 37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में प्याज, आलू तथा टमाटर की कीमतें क्रमशः 53, 50 और 18 प्रतिशत बढ़ीं। इसकी वजह प्याज तथा आलू की कम आवक, जबकि भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में टमाटर का उत्पादन प्रभावित रहना रही है।

उत्पादन में कमी से दालों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि साल की शुरुआत में कीमतों में कटौती के कारण ईंधन की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं, मांसाहारी थाली भोजन के प्रतिशत घटकर 59.3 रुपये हो गई, जबकि ब्रायलर (मांस) की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका इस थाली में 50 प्रतिशत योगदान है। अगस्त की तुलना में मांसाहारी थाली की लागत स्थिर रही है।

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा प्लेटफार्म बना जेम पोर्टल, हजारों करोड़ का हो रहा कारोबार

परिवहन विशेष न्यूज़

पीएम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया अवधारणा के तहत सितंबर 2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कारोबार में नवाचार के जरिए बुनियादी ढांचे का विकास करना ताकि देश की प्रगति को सहारा मिल सके। पोर्टल में उत्पादों को सूचीबद्ध करने के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता देना आसान हो गया है।

नई दिल्ली। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने पिछले आठ वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत बाजार के अवसरों को पारदर्शी बनाया है। बिचौलिये प्रणाली को खत्म कर नई तकनीक के जरिए स्टार्टअप एवं छोटे कारोबारियों को बड़ा प्लेटफार्म दिया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ ही महिला उद्यमियों को भी बाजार में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है। अभी तक साढ़े 26 हजार से ज्यादा स्टार्टअप जेम के माध्यम से 29 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 में जेम पोर्टल पर स्टार्टअप द्वारा 97 हजार से अधिक के आर्डर पूरे किए गए।

2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' अवधारणा के तहत सितंबर 2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था कारोबार में नवाचार के जरिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, ताकि देश की प्रगति को सहारा मिल सके। पोर्टल में उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निर्माताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना आसान हो गया है।

सहकारी समितियों के कारोबारी दायरे का विस्तार किया है।
तेजी से बढ़ रहा जेम पोर्टल
जेम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण ने बताया कि पांच लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली बोलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महज तीन वर्ष पहले तक जेम पोर्टल पर सरकारी संस्थाओं द्वारा मंगाई गई 39 प्रतिशत बिड 'मेक इन इंडिया' की थी, जो अब बढ़कर (सितंबर 2024 तक) 81 प्रतिशत हो गया।
चव्हाण के मुताबिक लेनदेन शुल्क में कटौती सबके लिए समान अवसर पैदा करने का प्रयास है, ताकि सार्वजनिक खरीद की सहज प्रणाली

विकसित की जा सके। जेम की सामान्य शर्तों के तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में खरीदारी पोर्टल पर निर्बाध विक्रेताओं से करने की बाध्दता है। राज्यों से भी आग्रह किया जा रहा है कि जेम पोर्टल की प्रणाली को अपनाएं। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए जेम पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी उपलब्ध है, ताकि खरीदारों को उत्पादों की जानकारी आसानी से हो सके। लेनदेन शुल्क में भारी कटौती

छोटे उद्यमों को बड़ी राहत

जेम ने छोटे उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए अपने लेनदेन शुल्क को एक ही इंटके में 96 प्रतिशत तक कम कर दिया है। दस लाख से कम के आर्डर पर कोई शुल्क नहीं है। पहले यह सीमा पांच लाख थी। पिछले वर्ष 97 प्रतिशत लेन-देन पर सूच्य शुल्क लगा है। दस लाख से दस करोड़ तक के आर्डर पर आर्डर मूल्य का मात्र 0.30 प्रतिशत शुल्क ही लगाया जाएगा। पहले 0.45 प्रतिशत लागत था। दस करोड़ रुपये से अधिक के आर्डर पर अधिकतम तीन लाख का शुल्क देना होगा, जो पहले 72.5 लाख था। अधिकतम शुल्क तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगा, चाहे आर्डर का आकार कुछ भी हो।

जल्द दोगुनी होगी आम आदमी की आय, जीवन स्तर में भी होगा सुधार; वित्त मंत्री ने दिलाया भरोसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले दो दशकों तक भारत में युवाओं की संख्या बढ़ेगी जबकि इस दौरान कई विकासशील देशों की जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। इससे भारत में खपत भी बढ़ेगा उत्पादकता भी बढ़ेगी व निवेश भी बढ़ेगा। मध्यम वर्ग की तेजी से बढ़ती संख्या उपभोग को बढ़ाएगा। रिसर्व में भारत की क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले समय में एक आम भारतीय के जीवन स्तर में काफी व्यापक सुधार होने जा रहा है। सरकार की आर्थिक नीतियां, तेज आर्थिक विकास दर, युवा शक्ति की बढ़ती संख्या, तकनीक पर जोर और कुछ हद तक मौजूदा वैश्विक हालात को कांफिडेंस है, जो आम भारतीयों के जीवन स्तर को गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे।
तीसरे कौटिल्या इकोनॉमिक कान्फ्लेव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राजकोषीय घाटा को इस वर्ष घटा कर 4.9 फीसद पर लाने को लेकर प्रबल है और इसके साथ ही सरकारी खर्चों की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार की कोशिश की जाएगी ताकि देश में वित्तीय अनुशासन बेहतर हो सके।
सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार कुछ ही वर्षों में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। यह कोशिश तब हो रही है जब वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा अस्थिरता है और मौजूदा तनावों की स्थिति ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीयों के जीवनस्तर में बहुत ही तेजी से सुधार होने वाला है और यह भारतीयों के



लिए रहने का ऐतिहासिक काल होगा। वित्त मंत्री ने आईएमएफ के हाल में एक अनुमान का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 75 वर्षों में 2730 डॉलर हुई है लेकिन सिर्फ अगले पांच वर्षों में इसमें दो हजार डॉलर की वृद्धि होगी। भारत जब वर्ष 2047 में अपनी आजादी का 100 वीं वर्षगांठ बनाएगा तब भारतीयों को एक विकसित देश के समान माहौल मिलेगा। भारत की विकास यात्रा में यहां की युवाशक्ति का बहुत ही योगदान होगा। सीतारमण ने कहा कि अगले दो दशकों तक भारत में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, जबकि इस दौरान कई विकासशील देशों की जनसंख्या में

बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। इससे भारत में खपत भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी व निवेश भी बढ़ेगा। मध्यम वर्ग की तेजी से बढ़ती संख्या उपभोग को बढ़ाएगा। अन्वेषण में भारत की क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर में भारत की उपलब्धि इसका नतीजा है। इसके साथ ही भारत का वित्तीय क्षेत्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है जो नई जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार है। इसके साथ ही वैश्विक हालात से भी भारत को मदद मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्रों के लिए एक मजबूत व उन्नत सपनाई चैन श्रृंखला के तौर पर भारत स्थापित होने लगा है।

